नवम्बर , 2023, वर्ष : 44 अंक : 11

www.indiatibet.net

तिब्बत की पहली हिन्दी समाचार पत्रिका

# तिब्बत देश

मूल्य :10 रू , वार्षिक : 100 रू

नवम्बर, 2023, वर्ष : 44 अंक : 11

# तिब्बत देश

तिब्बत की पहली हिन्दी समाचार पत्रिका पहली बार 1979 में प्रकाशित तिब्बत के बारे में सही जानकारी के साथ हर महीने आपके हाथो में

सिक्यांग पेंपा छेरिंग और कनाडा के मंत्री और संसद के साथ।

**प्रधान संपादक**
**जमयंग दोरजी, थुप्तेन रिन्ज़ीन**

**सलाहकार संपादक**
प्रो. श्यामनाथ मिश्र , डा. अतुल कुमार

**प्रबंध संपादक**
तेनजिन जोरदेन

**वितरण प्रबंधक**
**छोन्यी छरिंग, ताशी देकि**

**संपादकीय एवं प्रकाशन कार्यालय :**
भारत तिब्बत समन्वय केन्द्र
एच -१० लाजपत नगर -३
नई दिल्ली -११००२४, भारत

तिब्बत देश में प्रकाशित विचरों से संपादक, प्रकाशक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है।

इसमें प्रकाशित सामग्री का उपयोग अन्यत्र किया जा सकता है। कृपया तिब्बत देश का उल्लेख अवश्य करें ।

## समाचार -


- यूरोपीय प्रचारकों के साथ शांति के लिए बैठक 1
- कनाडाई सांसद जेम्स मैलोनी ने कनाडाई संसद में सिक्योंग पेन्पा छेरिंग का स्वागत किया 2
- सिक्योंग पेंपा छेरिंग ने तिब्बत के समर्थन में ओटावा में मंत्रियों, सांसदों और तिब्बत समर्थकों से मुलाकात की 3
- सिक्योंग पेंपा छेरिंग ने ओटावा यात्रा के दौरान तिब्बत का मुद्दा उठाया 4
- १६वें कशाग ने स्थायी रणनीति समिति की पाचवीं बैठक बुलाई 5
- प्रेस विज्ञप्ति : सीटीए ने तिब्बती संसद की विदेश मामलों की समिति (एचएफएसी) द्वारा 'रिज़ॉल्व तिब्बत बिल' की मंजूरी का स्वागत किया 6
- चीन ने तिब्बती छात्रों से दलाई लामा की निंदा करने का आग्रह किया 'अलगाववाद विरोधी' कार्यशाला में शिक्षकों और छात्रों को एकदलीय शासन के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा करने के लिए कहा जाता है। 7
- तिब्बत में बौद्ध भिक्षु को चीनी अधिकारियों द्वारा हिरासत में लिए जाने की पुष्टि बौद्ध भिक्षु को कथित तौर पर क्षेत्र के बाहर के लोगों से संपर्क करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 8
- जर्मनी की आधिकारिक यात्रा पर हैं डिप्टी स्पीकर डोल्मा छेरिंग तेखांग 9
- कालोन नोरज़िन डोल्मा की ऑस्ट्रेलिया की पहली यात्रा का ऑस्ट्रेलियाई सीनेट में जोरदार स्वागत 10


## समाचार -


- बेल्जियम संघीय संसद के विदेश मामलों की समिति की अध्यक्ष ने तिब्बती बच्चों के साथ ज़्यादती बंद करने का आह्वान किया 11
- ऑस्ट्रेलियाई सर्वदलीय संसदीय तिब्बत समूह ने विदेश मंत्री पेनी वोंग को पत्र लिखकर चीन पर संयुक्त राष्ट्र की आवधिक समीक्षा में तिब्बत का मुद्दा उठाने का आग्रह किया 12
- दिल्ली आईआईएमसी के पत्रकारिता छात्रों ने सीटीए शैक्षणिक दौरा किया 13
- टीएसजी अरुणाचल प्रदेश ने ताढ़ तारक को नए अध्यक्ष और नीमा सांगे को महासचिव चुना 14
- 'तिब्बत मुक्त करो, भारत बचाओ' के उद्घोष के साथ पांचवीं जनजागरण साइकिल यात्रा पश्चिम बंगाल के कोलकाता से शुरू 15
- जापान, तिब्बत, उग्यूर और दक्षिणी मंगोलिया ने चीन के कुख्यात धार्मिक आदेश संख्या- १९ की निंदा में सेमिनार आयोजित किया 16
- अरुणाचल प्रदेश के तिब्बत समर्थक समूह ने ईटानगर में कार्यकारी निकाय की बैठक आयोजित की 17
- तिब्बत पर्यावरण सम्मेलन में प्रतिनिधियों ने नदी की चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक प्रयास की शपथ ली 18
- भारत-तिब्बत समन्वय कार्यालय ने गुवाहाटी में तिब्बत समर्थक समूहों के साथ बैठक की 19
- भारत- तिब्बत सहयोग मंच के असम प्रांत ने १२वीं तवांग तीर्थ यात्रा का आयोजन किया 20
- जैसे ही तिब्बत जिजांग बना कि दिल्ली को एक नई समस्या का सामना करना पड़ेगा 21


मुद्रक एवं प्रकाशक
जमयांग दोरजी द्वारा
नोरबू ग्राफ़िक्स , 1/6, बेसमेंट
विक्रम विहार , लाजपत नगर
नई दिल्ली - 110024

तिब्बत के बारे में नियमित जानकारी के लिए भारत - तिब्बत समन्वय केन्द्र की वेबसाइट
www.indiatibet.net
Email:
indiatibet7@gmail.com

**अपनी बात**

# ◆ तिब्बत समर्थक संगठनों की विस्तारवादी चीन को कठोर चेतावनी

तिब्बती संघर्ष यात्रा में शामिल विभिन्न समर्थक संगठनों की स्पष्ट चेतावनी है कि विस्तारवादी चीन सरकार अपनी हठधर्मिता छोड़कर तिब्बत समस्या का समाधान शीघ्र करे। वर्ष 1959 में साम्राज्यवादी चीन ने स्वतंत्र देष तिब्बत को पूरी तरह अपने अवैध नियंत्रण में ले लिया था। तिब्बत के परतंत्र होते ही भारत के साथ चीन की सीमा जुड़ गई। ऐसा नहीं होता तो कभी भी भारत एवं चीन के बीच सीमा विवाद नहीं होता। चीन द्वारा सन् 1962 में भारत पर आक्रमण नहीं होता। हजारों वर्गमील भारतीय भूभाग पर उपनिवेषवादी चीन का अवैध कब्जा इसी का परिणाम है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों को चीनी भूभाग बताने का चीनी षड्यंत्र अब भी जारी है। अच्छा हुआ कि 14 नवंबर, 1962 को भारतीय संसद ने सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित कर चीनी चंगुल से भारतीय भूभाग को मुक्त कराने का संकल्प ले रखा है। इसे हर समय प्रकाषित-प्रचारित-प्रसारित करते रहना है।

जैसे ही चीन ने तिब्बत में घुसपैठ शुरू की अनेक भारतीय राजनेताओं, चिंतकों तथा संगठनों ने तत्कालीन नेहरू सरकार को सावधान करना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री नेहरू ने किसी की न सुनी और "हिन्दी चीनी भाई-भाई", "पंचषील" तथा "शांति के प्रतीक सफेद कबूतर उड़ाने" में लगे रहे। चीन की भारतविरोधी सामरिक-कूटनीतिक तैयारी का उनका जवाब यही था। इसी के परिणामस्वरूप प्रधानमंत्री नेहरू को सावधान करने वालों की प्रत्येक आषंका लगातार सही साबित हो रही है। सरदार पटेल, जयप्रकाष नारायण, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉ. राममनोहर लोहिया आदि चिंतक विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं से जुड़े थे। इसके बावजूद तिब्बत संबंधी विचार सबके एक समान थे। उनके अनुसार तिब्बत पर चीनी नियंत्रण के समय भारत की चुप्पी से भारतीय "शांति-समृद्धि-सुरक्षा-स्वाभिमान" के लिये दीर्घकालीन खतरा हो गया।

तत्कालीन भारतीय विचारकों से प्रभावित संगठन एवं व्यक्ति आज भी तिब्बती संघर्ष में सक्रिय हैं। भारत तिब्बत मैत्री संघ, भारत तिब्बत सहयोग मंच, भारत तिब्बत संघ तथा हिमालय परिवार इसी के उदाहरण हैं। हिमालयन कमेटी फॉर एक्सन ऑन तिब्बत (हिमकैट), सुरुचि कला समिति एवं हिमालय बौद्ध संस्कृति संरक्षण सभा समेत कई संगठन तिब्बती संघर्ष में सहयोगी हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक इन्द्रेष कुमार, समाजषास्त्री प्रो. आनंद कुमार, श्रद्धेय गेषे लामा चोसफेल जोत्पा, मालिंग गोंबू एवं सोनम लुंडुप यथाशक्ति नई पीढ़ी को तिब्बती आंदोलन में सफलतापूर्वक जोड़ रहे हैं। महिला, युवा, पत्रकार, पूर्व सैनिक, पूर्व सरकारी अधिकारी, अधिवक्ता आदि प्रभावी वर्गों की भागीदारी सुनिष्चित करने के लिये इनकी विषेष शाखायें संचालित हैं। भारत तिब्बत समन्वय केन्द्र के प्रयासों से भारत स्थित तिब्बत समर्थक संगठन कई प्रकार के रचनात्मक, संघर्षात्मक तथा प्रतिनिधित्वात्मक कार्यक्रम कर रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ, 2013 के समय लामा चोसफेल जोत्पा के मार्गदर्षन में हिमकैट द्वारा व्यापक पैमाने पर साहित्य वितरण कर जागरुकता अभियान चलाया गया था। इस प्रकार के अभियान लगातार जारी हैं। पूर्व लोकसभाध्यक्ष रवि राय तथा भारत के पूर्व स्वतंत्रता सेनानी अमरकृष्ण व्यास से प्रेरित-प्रभावित व्यक्ति सामाजिक जीवन के जिस क्षेत्र में भी हैं, तिब्बती संघर्ष के साथ हैं। अमरकृष्ण व्यास तो भारत एवं तिब्बत दोनों के स्वतंत्रता सेनानी थे।

परमपावन दलाई लामा, श्रद्धेय प्रो. सामदोंग रिंपोछे तथा भारत स्थित निर्वासित तिब्बत सरकार का मत है कि चीन सरकार तिब्बत को "वास्तविक स्वायत्तता" प्रदान करे। चीन के संविधान एवं राष्ट्रीयता संबंधी कानून में ऐसा प्रावधान है। चीन अपने पास प्रतिरक्षा एवं विदेषनीति रखे तथा षिक्षा, संस्कृति कृषि आदि अन्य विषय तिब्बतियों को सौंप दे। अभी चीन ने तिब्बत के विभिन्न क्षेत्रों को चीनी भूभाग में शामिल कर रखा है और यही "तथाकथित स्वायत्तता" है। इसके बदले "वास्तविक स्वायत्तता" की मांग हो रही है।
तिब्बत समर्थक संगठन तिब्बत की पूर्ण स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। इसके बावजूद वे तिब्बत के लिये "वास्तविक स्वायत्तता" की मांग से सहमत हैं। इसका कारण है तिब्बत का षड्यंत्रपूर्ण चीनीकरण। पूर्ण स्वतंत्रता से अधिक जरूरी है तिब्बती पहचान का संरक्षण। पूरा विष्वजनमत "वास्तविक स्वायत्तता" अर्थात् "मध्यममार्ग" के साथ है। इस समाधान से चीन की संप्रभुता सुरक्षित रहेगी और चीन के अंदर ही तिब्बतियों को स्वषासन का अधिकार मिल जायेगा।

भारत में ऑल पार्टी इंडियन पार्लियामेंटरी फोरम फॉर तिब्बत ने प्रारम्भ से ही तिब्बती संघर्ष को संसद और सड़क पर समानरूप से चलाया है। ऐसा ही ऑस्ट्रेलियन ऑल पार्लियामेंटरी ग्रुप फॉर तिब्बत तथा यूरोपियन पार्लियामेंटरी डेलिगेसन द्वारा किया जा रहा है। विभिन्न देषों में स्थित तिब्बत सरकार के कार्यालय वहाँ की सरकारों तथा विभिन्न सरकारी एवं गैरसरकारी संगठनों का सक्रिय सहयोग और समर्थन प्राप्त कर रहे हैं।

ऐतिहासिक रूप से भारत का पड़ोसी तिब्बत है इसलिये हमारी सरकार भारतीय हितों की दृष्टि से तिब्बत नीति अपनाते हुए चीन सरकार पर दबाव बढ़ाये। भारत सरकार के ठोस कदम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तिब्बती संघर्ष सषक्त होगा। विष्व के अधिकांष देष इसकी प्रतीक्षा में हैं। तिब्बत संकट के प्रारम्भ में ही हमारे चिंतकों ने बता दिया था कि तिब्बत की आजादी भारत की सुरक्षा के लिये जरूरी है। उनके दिये इस अचूक मंत्र को भारतीय कूटनीति में उपयुक्त स्थान मिलना चाहिये। चीन के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत सरकार तिब्बत के सवाल को गंभीरतापूर्वक उठाये। भारत एवं विष्व के विभिन्न देषों में सक्रिय तिब्बत समर्थक संगठनों की भारत सरकार से यही अपील है। तिब्बत समस्या का समाधान संपूर्ण विष्व, विषेषकर भारत एवं समस्त हिमालय क्षेत्र के हित में है।

प्रो0 श्यामनाथ मिश्र
पत्रकार एवं अध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खेतड़ी (राजस्थान)

मो.-9079352370, 8764060406
E-mail & Facebook: - shyamnathji@gmail.com

## ◆ यूरोपीय प्रचारकों के साथ शांति के लिए बैठक

dalailama.com, ०८ नवंबर, २०२३

**थेकचेन छोलिंग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश, भारत।** परम पावन दलाई लामा ने ०८ नवंबर की सुबह शांति प्रचारकों के एक समूह से मुलाकात की। इस समूह में ज्यादातर प्रचारक यूरोप से थे। इस समूह की नेता फ्रांस की सोफिया स्ट्रिल-रेवर ने घोषणा की कि परम पावन से दूसरी बार मिलने के बाद उनका दिल खुशी से भर गया है। सोफिया ने कहा कि उनका समूह मानवता की सेवा में परम पावन द्वारा स्थापित उदाहरण से प्रेरित है। उन्होंने बताया कि समूह ने ०५ अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र समर्थित 'अंतरात्मा की आवाज दिवस' कार्यक्रम में भाग लेने का फैसला किया है। यह कार्यक्रम सभी लोगों के लिए बिना किसी भेदभाव के मौलिक स्वतंत्रता और मानवाधिकार स्थापित करने के लिए समर्पित है।

स्ट्रिल-रेवर ने परम पावन से पूछा कि अंतरात्मा की आवाज और प्रेम विश्व में स्थायी शांति में कैसे योगदान दे सकता है?

इस पर परम पावन ने उत्तर दिया- 'जन्म लेते ही हम सभी को माँ का प्यार मिलता है। छोटे बच्चे के रूप में हम बेझिझक दूसरे बच्चों के साथ खेलते हैं। इस समय हम इसकी परवाह नहीं करते कि वे कहां से हैं या उनका या उनके परिवार की वैचारिक पृष्ठभूमि क्या है। इस प्रकार का खुलापन हमारे मूल मानव स्वभाव का हिस्सा है।

उन्होंने कहा कि वयस्क होने पर हममें से बहुत से लोग अन्य लोगों को 'हम' और 'वे' के संदर्भ में देखते हैं। हमारे बीच के राजनीतिक या धार्मिक मतभेदों के आधार पर हमारे बीच भेदभाव होता है। यदि हमें अपने बीच की शांति में योगदान देना है तो हमें मूल रूप से मनुष्य के रूप में हम सभी को एक समान होने के तरीके खोजने होंगे। हम एक समान अनुभव रखते हैं। हम एक ही तरह से पैदा होते हैं और अंततः हम सभी एक तरीके से ही मर जाते हैं।

राष्ट्रीयता की पहचान या आस्था में मतभेद एक-दूसरे को मारने का बहाना बन जाता है। यह अकल्पनीय है। यहां तक कि जानवर भी अधिक शांतिपूर्वक एक साथ रहते हैं। अगर चीज़ें बदलनी हैं तो हम आठ अरब मनुष्यों को इस ग्रह पर

एक साथ रहना सीखना होगा। हमें अपनी सामान्य मानवीय चरित्र को पहचानना चाहिए। इसीलिए जब भी मैं किसी नए व्यक्ति से मिलता हूं तो मैं हमेशा उन्हें अपने जैसे इंसान के रूप में देखता हूं। इस तरह मैं मानता हूं कि हम सभी एक मानव परिवार के सदस्य हैं।'

जलवायु संकट के बारे में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए परम पावन ने टिप्पणी की कि जो परिवर्तन हो रहे हैं वे हमारे नियंत्रण करने की क्षमता से परे प्रतीत होते हैं। उन्होंने दोहराया कि मनुष्य के रूप में हम सभी एक समान हैं और हमें न केवल एक साथ रहना सीखना चाहिए बल्कि अपने सामूहिक हित में एक साथ काम करना भी सीखना चाहिए।

उन्होंने आगे कहा, 'हालांकि हमारे पास अभी भी समय है। इसमें भाईचारे और भाईचारे की भावना पैदा करना और एक-दूसरे की मदद करने की भावना से काम करने में ही समझदारी होगी। हमें उस बुनियादी मानवीय प्रेम को बढ़ाने का एक तरीका खोजने की जरूरत है जो हमारी मां हमें जन्म के समय सिखाती है और इसे जीवन भर दूसरों तक पहुंचाती है।'

यह पूछे जाने पर कि धर्म विश्व के भविष्य को कैसे प्रभावित कर सकता है, परम पावन ने उत्तर दिया- 'धर्म का सार सौहार्द है। सभी धर्म यही सिखाते हैं, चाहे वे कोई भी दार्शनिक रुख अपनाने वाले हों। सौहार्दता ही सार है, इसे विकसित करने में ही कल्याण है।'

## ◆ कनाडाई सांसद जेम्स मैलोनी ने कनाडाई संसद में सिक्योंग पेन्पा छेरिंग का स्वागत किया

tibet.net, २३ नवंबर, २०२३

**कनाडा।** वर्तमान में कनाडा की आधिकारिक यात्रा पर गए केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेन्पा छेरिंग का बुधवार, २२ नवंबर २०२३ को कनाडाई संसद में औपचारिक रूप से स्वागत किया गया। कनाडाई सांसद जेम्स मैलोनी ने निर्वासित तिब्बती प्रशासन के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नेता का स्वागत उनकी उपस्थिति में किया। स्पीकर ग्रेग फर्गस और सदन के सदस्य सांसद मैलोनी ने सिक्योंग पेन्पा छेरिंग का हार्दिक स्वागत किया। उन्होंने कहा कि वह 'दुनिया और कनाडा में तिब्बतियों की आवाज़ हैं'।

उन्होंने सदन को कनाडा में रहने वाले हजारों तिब्बतियों की जीवंत संस्कृति से अवगत कराया। इस तरह के महत्वपूर्ण अंतर्सांस्कृतिक पहलू के संबंध में सांसद मैलोनी ने कहा कि एटोबिकोक लेकशोर में स्थित तिब्बती-कनाडाई सांस्कृतिक केंद्र का प्रमुख लक्ष्य बौद्ध धर्म का संरक्षण और सभी संस्कृतियों से परे सद्भावपूर्ण जीवन के लिए सम्मान और इसे प्रतिबिंबित करना है। उन्होंने टिप्पणी की कि 'इसके अतिरिक्त अहिंसा और शांति पूरी मानवता के लिए सार्वभौमिक आकांक्षाएं हैं। उन्होंने कहा कि सिक्योंग उन मूल्यों के प्रतीक हैं। उन्होंने कड़ी मेहनत और प्रयास के लिए सिक्योंग की भूरि-भूरि प्रशंसा की और सिक्योंग और तिब्बत के लोगों के साथ खड़े होने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की और समर्थन का आश्वासन दिया।

## ◆ सिक्योंग पेंपा छेरिंग ने तिब्बत के समर्थन में ओटावा में मंत्रियों, सांसदों और तिब्बत समर्थकों से मुलाकात की

tibet.net, २३ नवंबर, २०२३

**धर्मशाला।** केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) के सिक्योंग पेन्पा छेरिंग ने ओटावा में कई सांसदों, सरकारी अधिकारियों और तिब्बत समर्थकों से मुलाकात कर उनसे बातचीत की। उनकी इस मुलाकात में तिब्बत मुक्ति साधना के लिए समर्थन जुटाना और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के कब्जे में कराह रहे तिब्बत में मानवाधिकार उल्लंघन का मुद्दा उठाना प्रमुख मुद्दा था। इस समय सिक्योंग तीन दिवसीय हैलिफ़ैक्स अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा फोरम-२०२३ को संबोधित करने के लिए उत्तरी अमेरिका के दौरे पर थे।

१९ नवंबर को निर्वासित तिब्बतियों द्वारा लोकतांत्रिक रूप से चुने गए नेता का कनाडा की राजधानी पहुंचने पर कनाडा- तिब्बत समिति के निदेशक शेराप थेरचिन और ओटावा-तिब्बती समुदाय संघ के कार्यकारी सदस्यों ने गर्मजोशी से स्वागत किया।

इसके बाद सिक्योंग पेन्पा छेरिंग ने ब्लॉक क्यूबेकॉइस के नेता सांसद फ्रेंकोइस ब्लैंचेट, सांसद एलेक्सिस ब्रुनेले और सांसद जूली विग्रोला से मुलाकात की और बातचीत की। उन्होंने 'कैनेडियन पार्लियामेंट्री फ्रेंड्स ऑफ तिब्बत' के अध्यक्ष सांसद आरिफ विरानी (कनाडा के न्याय मंत्री और अटॉर्नी जनरल), लंबे समय से तिब्बत समर्थक और 'पार्लियामेंट्री फ्रेंड्स ऑफ तिब्बत' के उपाध्यक्ष सांसद गार्नेट जेनुइस और ओटावा फ्रेंड्स ऑफ तिब्बत के सदस्यों से भी मुलाकात की। इन बैठकों के दौरान निर्वासित तिब्बती प्रशासन के प्रमुख ने पूरे तिब्बती समुदाय की ओर से समर्थकों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और उनके साथ तिब्बत के लिए कनाडा के समर्थन को मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने सांसदों और समर्थकों के साथ बातचीत में अन्य मुद्दों के अलावा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के कब्जे में कराह रहे तिब्बत में मानवाधिकारों की स्थिति के बारे में भी उन्हें जानकारी दी।

दौरे पर आए तिब्बती नेता की विदाई में 'कैनेडियन पार्लियामेंट्री फ्रेंड्स ऑफ तिब्बत' द्वारा एक समारोह का भी आयोजन किया गया। मंत्री गैरी आनंदसांगारे, मंत्री कमल खेड़ा, मंत्री आरिफ विरानी, मंत्री डोमिनिक लेब्लांक, स्पीकर ग्रेग फर्गस, सांसद जेम्स मैलोनी, सांसद यवन बेकर, सांसद ब्रायन मे, सांसद फ्रांसेस्को सोरबारा, सांसद ब्रेंडन हैनली, सांसद जैमे बैटिस्ट, सांसद पॉल चियांग, सांसद रयान टर्नबुल, सांसद समीर जुबेरी, सांसद परम बैंस, सांसद फैकल एल-खौरी, सांसद जोएल लाइटबाउंड, सांसद जूडी एसग्रो, सांसद जॉन विलियम्स, सांसद कोडी ब्लोइस, सांसद डेविड मैकगिन्टी, सांसद एडम वैन कोवेरडेन, सांसद गार्नेट जेनुइस, सांसद रॉब ओलिफंट, सांसद ब्रेंडा शानहन और सांसद जूली विग्रोला इस समारोह में शामिल हुईं।

इस कार्यक्रम में सिक्योंग पेन्पा छेरिंग के साथ वाशिंगटन डीसी स्थित तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि डॉ. नामग्याल चोएडुप और कनाडा-समिति के निदेशक शेराप थेरचिन भी थे।

## ◆ सिक्योंग पेंपा छेरिंग ने ओटावा यात्रा के दौरान तिब्बत का मुद्दा उठाया

tibet.net, २७ नवंबर, २०२३

**ओटावा।** केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) के सिक्योंग पेन्पा छेरिंग ने २० से २३ नवंबर, २०२३ तक ओटावा में अपने चार दिवसीय कार्यक्रम के दौरान सांसदों, सरकारी अधिकारियों, थिंक टैंक प्रतिनिधियों, सामुदायिक संगठनों से मुलाकात बैठकें कीं और मीडिया को साक्षात्कार दिया।

अपने कार्यक्रमों के दौरान लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नेता ने कनाडा के सभी राजनीतिक दलों के ३२ सांसदों के साथ मिलकर बैठकें कीं। इनमें चार कैबिनेट मंत्री- आरिफ विरानी, डोमिनिक लेब्लांक, कमल खेड़ा और गैरी आनंदसंगारि शामिल थे। इसके अलावा सिक्योंग ने पार्लियामेंटरी फ्रेंड्स ऑफ तिब्बत के सह-अध्यक्षों- सांसद गार्नेट जेनुइस और सांसद जेम्स मैलोनी से मुलाकात की। उन्होंने वहां के विदेश मंत्री के संसदीय सचिव सांसद रॉब ओलिपांत और अंतरराष्ट्रीय विकास मंत्री की संसदीय सचिव सांसद अनीता वैंडेनबेल्ड के साथ भी चर्चा की।

सिक्योंग ने ब्लॉक क्यूबेकॉइस के नेता यवेस-फ्रेंकोइस ब्लैंचेट और सांसद एलेक्सिस ब्रुनेले-डुसेप और जूली विग्रोला के साथ बैठकों में उनकी पार्टियों द्वारा तिब्बत के लिए कनाडा के समर्थन को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा।
सिक्योंग ने कनाडाई सदन के स्पीकर माननीय ग्रेग फार्गस से मुलाकात कर उन्हें स्पीकर चुने जाने पर बधाई दी और तिब्बत में मानवाधिकारों की वर्तमान स्थितियों से उन्हें अवगत कराया।

इसी तरह सिक्योंग ने कनाडा के विदेश मंत्रालय- ग्लोबल अफेयर्स कनाडा के अधिकारियों के साथ तिब्बत में वर्तमान मानवाधिकारों की स्थिति पर भी चर्चा की, जिसमें तिब्बती बच्चों को उनके परिवारों से जबरन अलग कर आवासीय स्कूलों में डालने और तिब्बती लोगों को प्राप्त धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में चिंताएं शामिल थीं।

इसके अलावा, सिक्योंग ने सार्वजनिक नीति थिंक टैंक के साथ भी चर्चा की और पॉलिसी इनसाइट्स फोरम के अध्यक्ष गोरान सैमुअल पेसिक के साथ बैठक की, जिसका प्रबंध पॉलिसी इनसाइट्स फोरम के पूर्व सहयोगी और तिब्बत के मित्र अन्वेष जैन ने किया था।

ओटावा में तिब्बती समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत में सिक्योंग ने उन्हें वैश्विक तिब्बत पक्षधरता को मजबूत करने और तिब्बती भाषा और सांस्कृतिक शिक्षण के अवसरों की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए केंद्रीय तिब्बती प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। ओटावा में सिक्योंग के दौरे का मुख्य उद्देश्य भी यही था।
सिक्योंग ने अंतिम दिन २३ नवंबर को ओटावा में सांसदों-जेम्स मैलोनी, जॉन मैके, स्कॉट एंडरसन, जूडी सग्रो, अनीता वैंडेनबेल्ड और जूली विग्रोला के साथ दोपहर के भोजन के साथ अपने दौरे का समापन किया।
पूरे कार्यक्रम में सिक्योंग पेन्पा छेरिंग के साथ वाशिंगटन डीसी स्थित तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि डॉ. नामग्याल चोएडुप और कनाडा-तिब्बत समिति के निदेशक शेराप थेरचिन भी मौजूद रहे।

## ◆ १६वें कशाग ने स्थायी रणनीति समिति की पाचवीं बैठक बुलाई

tibet.net, ०८ नवंबर, २०२३

**धर्मशाला।** केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) के १६वें कशाग ने ०८ नवंबर की सुबह धर्मशाला में रणनीति समिति की पाचवीं बैठक आयोजित कीं।

यह तीन दिवसीय द्विवार्षिक बैठक पिछली चार बैठकों में तय किए गए उपायों के कार्यान्वयन के अनुरूप कार्य करेगी। इसके अलावा, बैठक में चल रहे रणनीतिक कार्यक्रमों की प्रगति पर चर्चा की जाएगी और समिति के उद्देश्यों के अनुसार भविष्य की पक्षधरता अभियानों के पहलों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

सिक्योंग पेन्पा छेरिंग बैठक की अध्यक्षता करेंगे जिसमें समिति के सदस्य शामिल होंगे। समिति सदस्यों में पूर्व कलोन टेम्पा छेरिंग, पूर्व कलोन डोंगचुंग न्गोडुप और पूर्व दूत केलसांग ग्यालछेन शामिल होंगे। उपस्थित प्रमुख हस्तियों में कलोन डोल्मा ग्यारी (सुरक्षा विभाग), कलोन नोरज़िन डोल्मा (सूचना और अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग), सचिव कर्मा रिनचेन (सुरक्षा विभाग), सचिव कर्मा चोयिंग (सूचना और अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग), सचिव दावा छेरिंग, तिब्बत नीति संस्थान (टीपीआई), कशाग सचिवालय के राजनीतिक सचिव ताशी ग्याछो और गाडेन फोडरंग कार्यालय के सचिव न्गाबा छेग्यम भी उपस्थित रहेंगे।

सूचना और अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग के सचिव चोयिंग ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा, 'यह बैठक रणनीतिक कार्यक्रमों की समीक्षा और चर्चा के अलावा चीन के औपनिवेशिक बोर्डिंग स्कूल और बड़े पैमाने पर डीएनए संग्रह से संबंधित तिब्बत में मौजूदा स्थिति, चीन के बदलते राजनीतिक परिदृश्य और वैश्विक समुदाय में इसके प्रभाव पर विचार-विमर्श करेगी।' उन्होंने यह भी कहा कि समिति इस साल सिक्योंग और वैश्विक नेताओं, सांसदों और बुद्धिजीवियों के बीच हुई आधिकारिक बैठकों पर भी चर्चा करेगी।

चीन-तिब्बत वार्ता के लिए गठित पिछली टास्क फोर्स के विघटन के बाद अगस्त-२०२१ में कशाग द्वारा स्थायी रणनीति समिति की स्थापना की गई थी। समिति ने अपनी पहली बैठक नवंबर-२०२१ में, दूसरी बैठक जुलाई- २०२२ में, तीसरी बैठक नवंबर- २०२२ में और चौथी बैठक अप्रैल- २०२३ में आयोजित की थी।

## ◆ प्रेस विज्ञप्ति : सीटीए ने तिब्बती संसद की विदेश मामलों की समिति (एचएफएसी) द्वारा 'रिज़ॉल्व तिब्बत बिल' की मंजूरी का स्वागत किया

tibet.net, २९ नवंबर, २०२३

**धर्मशाला।** केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) ने तिब्बती संसद की विदेश मामलों की समिति (एचएफएसी) द्वारा तिब्बत-चीन संघर्ष अधिनियम के प्रस्ताव को बढ़ावा देने वाले तिब्बत बिल एच.आर.- ५३३ की मंजूरी का स्वागत किया है। एचएफएसी ने २९ नवंबर २०२३ को मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए मतदान में सर्वसम्मति से दोनों दलों की सहमति वाले इस 'तिब्बत-चीन संघर्ष के समाधान को बढ़ावा देनेवाले अधिनियम' को पारित कर दिया। इस कानून को तिब्बत समाधान अधिनियम रूप में भी जाना जाता है।

एचएफएसी द्वारा अनुमोदित यह विधेयक इससे पहले अमेरिका के ओरेगन राज्य से डेमोक्रेट सीनेटर जेफ मर्कले और इंडियाना राज्य से रिपब्लिकन सीनेटर टॉड यंग के साथ-साथ प्रतिनिधि सभा में मैसाचूयूसेट्स राज्य से डेमोक्रेट सदस्य जिम मैकगवर्न और टेक्सास से रिपब्लिकन सदस्य माइकल मैककॉल द्वारा पेश किए गए कानून का सदन से संशोधित संस्करण है। यह विधेयक तिब्बत-चीन संघर्ष को हल करने के लिए पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और परम पावन दलाई लामा के प्रतिनिधियों या तिब्बती लोगों के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए नेताओं के बीच बिना किसी पूर्व शर्त के सीधी बातचीत का समर्थन करने की अमेरिकी आधिकारिक नीति को ही दोहराता है। २००२ से २०१० के बीच तक चीन और परम पावन के प्रतिनिधियों के बीच नौ दौर की बातचीत के बाद चीन ने बातचीत को रोक दिया। चीन ने इसकी जगह तिब्बत में तिब्बती भाषा, धर्म, संस्कृति और जीवन शैली को नष्ट करने के लिए औपनिवेशिक नीतियों और कार्यक्रमों की एक शृंखला की शुरुआत कर दी, जो तिब्बती लोगों की पहचान और अस्तित्व को खतरे में डाल रही है।

यह विधेयक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) के तिब्बत के प्राचीन काल से चीन का हिस्सा होने के दावे को ऐतिहासिक रूप से गलत बताकर खारिज करता है और विदेश विभाग को तिब्बत के इतिहास, संस्कृति और परम पावन दलाई लामा संस्था सहित तिब्बत की अन्य संस्थाओं के बारे में चीन की दुष्प्रचार का सक्रिय रूप से मुकाबला करने का अधिकार देता है।

'रिज़ॉल्व तिब्बत ऐक्ट' को आगे बढ़ाने के प्रयास में सिक्योंग पेन्पा छेरिंग ने इस साल १६ से २० अक्तूबर तक वाशिंगटन- डीसी का दौरा किया और उन्होंने ११८वीं अमेरिकी कांग्रेस से तिब्बत बिल के पारित होने की विशेष उम्मीदें व्यक्त कीं। सिक्योंग कहते हैं, 'पीआरसी का चीन का अंग बताते हुए तिब्बत पर दावा करना काल्पनिक है, क्योंकि इसमें कोई ऐतिहासिक सच्चाई नहीं है। पीआरसी सरकार के तहत कई दशकों में हम तिब्बतियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, फिर भी हमने हमेशा अहिंसक और शांतिपूर्ण बातचीत के माध्यम से अपने मतभेदों को सुलझाने की कोशिश की है।

सिक्योंग ने आगे कहा, 'यह विधेयक अमेरिका को अपने देश में तिब्बतियों को समर्थन देते हुए अधिक ताकत और तात्कालिकता के साथ बातचीत को जरूरी बताते हुए आह्वान करने की अनुमति देगा। इससे न केवल तिब्बतियों के हित को मदद मिलेगी, बल्कि दुनिया भर में लोकतंत्र, संवाद और शांति के हित को भी आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसलिए, हमें विश्वास है कि यह विधेयक कांग्रेस के दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति का अनुमोदन भी प्राप्त कर लेगा।'

'हम तिब्बत बिल को मंजूरी देने के लिए एचएफएसी के अध्यक्ष माइकल मैककॉल, रैंकिंग सदस्य ग्रेगरी मीक्स और समिति के सभी सदस्यों को धन्यवाद देते हैं। यह मंजूरी उस अविश्वसनीय द्विदलीय समर्थन के बल पर मिली है जो अमेरिका ने हमेशा हमारे उचित कारण के लिए दिखाया है।'

चीन ने तिब्बती छात्रों से दलाई लामा की निंदा करने का आग्रह किया

## ◆ 'अलगाववाद विरोधी' कार्यशाला में शिक्षकों और छात्रों को एकदलीय शासन के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा करने के लिए कहा जाता है।

rfa.org, ०६ नवंबर, २०२३

तिब्बत के अंदर रहने वाले दो तिब्बतियों ने बताया है कि चीन पश्चिमी तिब्बत में शिक्षकों और छात्रों से एकदलीय शासन-प्रशासन के प्रति निष्ठा व्यक्त करने और दलाई लामा और उनके अधिकारियों द्वारा परिभाषित अलगाववादी तरीकों की निंदा करने का आग्रह कर रहा है।

सूत्रों ने बताया कि अधिकारियों ने चीन के पश्चिमी तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के न्गारी प्रिफेक्चर से प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के ४०० से अधिक शिक्षकों और छात्रों को अक्तूबर में 'अलगाववाद विरोधी' कार्यशाला में भाग लेने के लिए बुलाया था।

एक तिब्बती ने लिखित संदेश में आरएफए को बताया, कार्यशाला में उपस्थित लोगों से कहा गया कि वे 'सरकार की विचारधारा के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करें और अलगाववाद और परम पावन दलाई लामा की निंदा करें।'उन्होंने लिखा, 'उपस्थित लोगों को स्कूलों में किसी भी धार्मिक गतिविधियों से दूर रहने के लिए भी कहा गया।'चीनी सरकार का मानना है कि दलाई लामा तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और पश्चिमी चीन के तिब्बती आबादी वाले क्षेत्रों को देश के बाकी हिस्सों से अलग करना चाहते हैं।

हालांकि, तिब्बती बौद्ध धर्म के निर्वासित आध्यात्मिक धर्मगुरु ने स्वतंत्रता की वकालत नहीं की है, बल्कि एक 'मध्यम मार्ग' की अवधारणा पेश की है जो तिब्बत को चीन के एक हिस्से के रूप में स्वीकार करता है और तिब्बत के लिए अधिक सांस्कृतिक और धार्मिक स्वायत्तता का आग्रह करता है, जिसमें चीनी संविधान के प्रावधानों के तहत नस्लीय अल्पसंख्यकों के लिए मजबूत भाषा अधिकार की गारंटी शामिल है।

**सांस्कृतिक दमन**

तिब्बत में रहनेवाले एक दूसरे तिब्बती ने पुष्टि की कि कार्यशाला के दौरान तिब्बती शिक्षकों और छात्रों को चीनी सरकार के प्रति अपनी वफादारी और देशभक्ति की प्रतिज्ञा करने और धर्म से संबंधित कोई भी शिक्षा देने और पढ़ने-पढ़ाने से परहेज करने के लिए कहा गया।

उन्होंने एक लिखित संदेश में आरएफए को बताया, 'शिक्षकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे छात्रों को सरकार की विचारधारा के प्रति निष्ठा का पालन करना सिखाएं।'यह कदम तब उठाया गया है जब चीनी सरकार ने तिब्बती संस्कृति, भाषा और धर्म को दबाने और राज्य के प्रति देशभक्ति और वफादारी सुनिश्चित करते हुए चीन की बहुमत वाली प्रमुख हान नस्ल की आबादी में तिब्बती पहचान को जबरन विलय करने के अपने प्रयासों को तेज कर दिया है। आरएफए ने यह भी सूचना दी है कि अक्तूबर में सिचुआन प्रांत में तिब्बती समुदायों के बीच जातीय अल्पसंख्यक भाषा-शिक्षण पर सरकार की ओर से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

सूत्रों ने बताया कि कार्यशाला में भाग लेने के लिए जिन स्कूलों को बुलाया गया था, उनमें न्गारी गारज़ोंग मिडिल स्कूल, कुंग-फेन-सेन एलीमेंट्री स्कूल, न्गारी वोकेशनल मिडिल स्कूल, न्गारी मॉडल स्कूल और न्गारी चाइल्ड केयर सेंटर शामिल थे।

सीटीए के आधिकारिक थिंक टैंक- तिब्बत नीति संस्थान- के निदेशक दावा छेरिंग ने कहा कि यह पूरा प्रपंच लोगों को दलाई लामा, भारत के धर्मशाला स्थित केंद्रीय तिब्बती प्रशासन और निर्वासित तिब्बत सरकार की निंदा करने के लिए मजबूर करने के चीनी सरकार के प्रयासों का हिस्सा है। हालांकि अब तक प्रयास सफल नहीं हुए हैं।

उन्होंने कहा, 'हाल ही में हमने सरकारी मीडिया में दलाई लामा की निंदा करने में चीनी सरकार की ओर से थोड़ी ढील देखी थी। लेकिन चीनी सरकार ने एक बार फिर कठोर नीतियां लागू करना शुरू कर दिया जब (उसे) एहसास हुआ कि प्रयास और दमनकारी नीतियों के बावजूद दलाई लामा के प्रति तिब्बतियों की आस्था और श्रद्धा को खत्म करना असंभव होगा।'

तिब्बत में बौद्ध भिक्षु को चीनी अधिकारियों द्वारा हिरासत में लिए जाने की पुष्टि

## ◆ बौद्ध भिक्षु को कथित तौर पर क्षेत्र के बाहर के लोगों से संपर्क करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

rfa.org, ०८ नवंबर, २०२३

तिब्बत की स्थिति के बारे में जानकारी रखने वाले दो लोगों ने बताया कि चीनी अधिकारियों ने सुदूर-पश्चिमी क्षेत्र के गांसु प्रांत स्थित ताशी मठ से एक तिब्बती बौद्ध भिक्षु को बाहर के लोगों से कथित तौर पर संपर्क करने के आरोप में गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया है। सूत्रों ने बताया कि कुंचोक दक्पा को अक्तूबर के आखिरी सप्ताह में थेवो काउंटी के मठ से ले जाया गया था।

तिब्बत में रहने वाले एक तिब्बती ने कहा, 'कुंचोक दक्पा ने अतीत में भारत की यात्रा की थी और धर्मशाला स्थित कीर्ति मठ में अध्ययन किया था। 'उन्होंने कहा कि उनके हिरासत के स्थान के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

भारत के धर्मशाला में कीर्ति मठ तिब्बती आध्यात्मिक धर्मगुरु दलाई लामा और निर्वासित तिब्बती सरकार का केंद्रीय स्थान है।

उन्होंने कहा, 'हालांकि चीनी अधिकारी अतीत में अक्सर भिक्षु कुंचोक दक्पा को बुलाते थे और पूछताछ करते थे, लेकिन इस बार उन्हें गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया गया है।'

दक्पा की गिरफ्तारी तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और आसपास के चीनी प्रांतों के तिब्बती क्षेत्रों में चीनी अधिकारियों द्वारा धर्म, अभिव्यक्ति, आंदोलन और सभा करने की आजादी पर जारी प्रतिबंधों के बीच हुई है।

आरएफए ने पहले विदेशों में तिब्बती समुदायों को जानकारी प्रदान करने वाले स्वायत्त क्षेत्र के अंदर के सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट दी थी कि चीन बाहरी दुनिया में सूचना प्रवाह को बंद करने के लिए निर्वासित लोगों के साथ बातचीत कर रहे तिब्बत के तिब्बतियों पर नज़र रख रहा है।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान सरकार ने ऑनलाइन संचार पर नियंत्रण कड़ा कर दिया है। चीन सरकार का दावा है कि यह राष्ट्रीय एकता को कमजोर करता है। साथ ही सरकार ने कथित ऑनलाइन अपराधों के आरोप में कुछ तिब्बतियों को हिरासत में लिया है।

एक अन्य तिब्बती ने कहा कि स्थानीय अधिकारियों ने भिक्षु को लगातार परेशान किया और पूछताछ की, हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि चीनी पुलिस या सरकारी गुप्त एजेंटों ने उन्हें गिरफ्तार किया है या किसी अन्य एजेंसी ने।

उन्होंने कहा, 'कुंचोक दक्पा हमेशा कानून का पालन करने वाले व्यक्ति रहे हैं और कभी भी ऐसी राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं हुए हैं जो अराजकता पैदा कर सकती हों। वह ऐसे व्यक्ति हैं जिनका स्थानीय तिब्बती सम्मान करते हैं और प्रशंसा करते हैं।'

कीर्ति मठ की पढ़ाई पूरी करने के बाद दक्पा ने लगभग पांच वर्षों तक वहां प्रशासनिक कार्यालय में काम किया। २०१२ में वह तिब्बत लौट आए और तब से वह गांसु के यिपा टाउनशिप में ताशी मठ में शिक्षक के रूप में काम कर रहे थे।

## ◆ जर्मनी की आधिकारिक यात्रा पर हैं डिप्टी स्पीकर डोल्मा छेरिंग तेखांग

tibet.net, ०९ नवंबर, २०२३

**बर्लिन (जर्मनी)।** दक्षिण- एशियाई सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के हिस्सा के रूप में निर्वासित तिब्बती संसद की डिप्टी स्पीकर डोल्मा छेरिंग तेखांग ०५ से ११ नवंबर, २०२३ तक जर्मनी के अध्ययन दौरे पर हैं।

प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों में भारत के राज्यसभा सदस्य श्री सुजीत कुमार, श्रीलंका के संसद सदस्य डॉ. पी. सुदर्शिनी फर्नांडोपुल्ले, नेपाल की प्रतिनिधि सभा के सदस्य नगीना यादव, मालदीव के अड्डू शहर के मेयर और मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी के अली निज़ार, भूटान के संसद सदस्य शेरिंग छोमो और भारत की लोकसभा के सदस्य श्री बृजेन्द्र सिंह शामिल हैं।

०६ नवंबर २०२३ को प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को डॉ. हाबिल और जर्मन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल एंड सिक्योरिटी अफेयर्स (एसडब्ल्यूपी) में वरिष्ठ फेलो क्रिश्चियन वैगनर द्वारा दक्षिण एशिया के बारे में जर्मनी की राय (द जर्मन व्यूज़ ऑन साउथ एशिया) के बारे में जानकारी दी गई। इसके बाद एफएनएफ फॉर फ्रीडम के निदेशक मंडल के अध्यक्ष प्रो. कार्ल-हेंज पैके और एफएनएफ फॉर फ्रीडम के अंतरराष्ट्रीय विभाग के प्रमुख डॉ. रेने क्लैफ द्वारा 'जर्मनी और विदेश में फ्रेडरिक नौमान फाउंडेशन के कार्य' के बारे में बताया गया। डिप्टी स्पीकर डोल्मा छेरिंग तेखांग को अन्य दक्षिण एशियाई सांसदों के साथ जर्मन संसद-बुंडेस्टाग के दौरे पर भी ले जाया गया और बाद में शाम को जर्मन

बुंडेस्टाग की सदस्य क्रिस्टीन एशेनबर्ग-डुग्रस ने महिला सांसदों के लिए संसद भवन में रात्रिभोज का आयोजन किया।

अगले दिन, डिप्टी स्पीकर और प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों ने बर्लिन में आउटडोर और इनडोर इतिहास संग्रहालय- टोपोग्राफी ऑफ टेरर (आतंक की स्थलाकृति)- का दौरा किया और उसके बाद उन्हें संघीय वित्त मंत्री के संसदीय राज्य सचिव डॉ फ़्लोरियन टोनकर द्वारा 'जर्मन सरकार के काम और संघीय वित्त मंत्रालय के वर्तमान विषयों' से परिचित कराया गया। एफएनएफ, पॉट्सडैम के एशिया डेस्क प्रमुख चार्ल्स डु विनेज और एफएनएफ, पॉट्सडैम के एशिया डेस्क के डेनिएला सैका के साथ दोपहर के भोजन की बैठक में प्रतिनिधियों को 'एशिया में संघवाद और विकेंद्रीकरण के बारे में पांच विचार' की जानकारी दी गई। इसके बाद प्रतिनिधियों को विदेश व्यापार के मुख्य कार्यकारी, अंतरराष्ट्रीय और यूरोपीय आर्थिक मामलों के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य डॉ. वोल्कर ट्रेयर द्वारा 'जर्मन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की संरचना और एशिया के साथ जर्मन आर्थिक संबंधों' से परिचित कराया गया। डॉ वोल्कर जर्मन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड कथरीना विटके, डिवीजन साउथ एंड साउथ-ईस्ट एशिया-पैसेफिक, एपीए, ऑस्ट्रेलिया एंड एशिया-पैसेफिक कंफ्रेंस ऑफ जर्मन बिजनेस (एपीके) और जर्मन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रमुख भी हैं।

सभी कार्यक्रमों के बाद प्रश्नोत्तर सत्र हुए, जिसके दौरान डिप्टी स्पीकर डोल्मा छेरिंग तेखांग ने सम्मानित जर्मन अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए तिब्बत और तिब्बतीयों से संबंधित मुद्दों को उठाया और निर्वासित तिब्बती संसद की ओर से अपील पत्र दिए। उन्होंने उनमें से अधिकांश को निर्वासन में तिब्बती लोकतंत्र को देखने के लिए धर्मशाला आने का खुला निमंत्रण भी दिया।

०८ नवंबर को डिप्टी स्पीकर और अन्य प्रतिनिधि बर्लिन से मेन्ज़ के लिए रवाना हुए और वहां कार्यक्रम जारी रखेंगे। बर्लिन और मेन्ज़ का यह दौरा फ्रेडरिक नौमान फाउंडेशन फॉर फ्रीडम (एफएनएफ) द्वारा आयोजित किया गया है।

## ◆ कालोन नोरज़िन डोल्मा की ऑस्ट्रेलिया की पहली यात्रा का ऑस्ट्रेलियाई सीनेट में जोरदार स्वागत

tibet.net, १६ नवंबर, २०२३

**कैनबरा।** ऑस्ट्रेलिया के ग्रींस से सीनेटर जेनेट राइस ने गुरुवार १६ नवंबर को सीनेट को संबोधित करते हुए चीन-तिब्बत संघर्ष के समाधान के लिए अपने प्रस्ताव पर समर्थन मांगने आईं सीटीए की सूचना और अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग की कालोन (मंत्री) नोरज़िन डोल्मा की ऑस्ट्रेलिया की पहली यात्रा का जोरदार स्वागत किया।

कालोन की १६ नवंबर को संसद भवन की यात्रा के अवसर पर सीनेटर जेनेट राइस ने तिब्बत में तिब्बतियों के सामने आने वाली गंभीर स्थिति को उठाया और ऑस्ट्रेलियाई सरकार से जनवरी में आगामी यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू (यूपीआर) में तिब्बत का मुद्दा उठाने का आग्रह किया।

तिब्बत के लिए ऑस्ट्रेलियाई सर्वदलीय संसदीय समर्थक समूह ने संसद भवन में 'तिब्बत ब्रीफिंग' बैठक आयोजित की, जिसमें माननीय उपसभापति शेरोन क्लेडन, सह-अध्यक्ष सांसद सुसान टेम्पलमैन, सीनेटर डीन स्मिथ, सीनेटर जेनेट राइस और विभिन्न राजनीतिक दलों के कई अन्य सांसद शामिल हुए। बैठक के दौरान कालोन ने तिब्बत के अंदर मौजूदा गंभीर स्थिति, तिब्बतियों को ऑस्ट्रेलियाई सरकार से उम्मीदें और मध्यम मार्ग दृष्टिकोण के माध्यम से चीन-तिब्बत संघर्ष को हल करने के लिए केंद्रीय तिब्बती प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने जनवरी २०२४ में चीन पर संयुक्त राष्ट्र यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू (यूपीआर) में तिब्बत में मानवाधिकारों की बहाली के लिए मजबूत सिफारिशों की आवश्यकता पर भी बल दिया।

बैठक से पहले कालोन नोरज़िन ने छाया विदेश मंत्री साइमन बर्मिंघम और खुफिया और सुरक्षा पर संसदीय संयुक्त समिति के अध्यक्ष सांसद पीटर खलील के साथ तिब्बत के बारे में एक घंटे तक चर्चा की।

दोपहर बाद उन्होंने गार्जियन में ऑस्ट्रेलिया के विदेशी मामलों और रक्षा संवाददाता डैनियल हर्स्ट को साक्षात्कार दिया।

कल १५ नवंबर को कालोन ने ऑस्ट्रेलिया में एक अग्रणी विदेश नीति थिंक टैंक-लोवी इंस्टीट्यूट, सिडनी- का दौरा किया, जहां उन्होंने तिब्बत के अंदर की गंभीर स्थिति के बारे में बात की और चीनी सरकार द्वारा लागू की गई कठोर नीतियों जैसे कि धार्मिक अधिकारों और स्वतंत्रता को कम करने और औपनिवेशिक शैली के बोर्डिंग स्कूल में तिब्बती बच्चों को जबरन प्रवेश देने जैसी सबसे हालिया नीति को रेखांकित किया। उन्होंने मध्यम मार्ग दृष्टिकोण के माध्यम से चीन-तिब्बत संघर्ष के समाधान की मांग पर केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के प्रतिबद्ध रुख पर भी बात की। कालोन ने एशफील्ड, सिडनी में अपने फाउंडेशन में परम पावन दलाई लामा के लंबे समय के मित्र और तिब्बत के समर्थक रेव बिल क्रूज़ से भी मुलाकात की।

अपने कार्यक्रमों के तहत कालोन ने एसोसिएशन द्वारा आयोजित रात्रिभोज में सिडनी और कैनबरा के तिब्बती समुदाय के कार्यकारी सदस्यों से भी मुलाकात की। १७ नवंबर को कालोन नोरज़िन डोल्मा नेशनल प्रेस क्लब में मुख्य अतिथि के रूप में वी-टैग ऑस्ट्रेलिया रणनीतिक बैठक और वकालत प्रशिक्षण की शोभा बढ़ाएंगी। दो दिवसीय बैठक सह प्रशिक्षण में ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग ५० तिब्बती युवा भाग लेंगे।

१९ नवंबर को आगे के कार्यक्रमों के लिए न्यूजीलैंड जाने से पहले कालोन ऑस्ट्रेलिया-तिब्बत परिषद और सिडनी स्थित चीनी-तिब्बती मैत्री संघ और अन्य चीनी लोकतंत्र कार्यकर्ताओं के निदेशक मंडल की बैठकों में भाग लेंगी।

## ◆ बेल्जियम संघीय संसद के विदेश मामलों की समिति की अध्यक्ष ने तिब्बती बच्चों के साथ ज्यादती बंद करने का आह्वान किया

tibet.net, २० नवंबर, २०२३

**ब्रुसेल्स।** बेल्जियम संघीय संसद की विदेश मामलों की समिति की अध्यक्ष सुश्री वान होफ ने विश्व बाल दिवस के अवसर पर २० नवंबर २०२३ को अपने परिवारों से अलग कर चीनी सरकार द्वारा संचालित आवासीय स्कूलों में दस लाख तिब्बती बच्चों को जबरन भर्ती करने की निंदा की। उन्होंने तिब्बती भाषा, संस्कृति, धर्म और पहचान को मिटाने के उद्देश्य से लाई गई इस नीति को अस्वीकार्य बताया।

सुश्री वान हूफ ने पीआरसी अधिकारियों से सरकार द्वारा संचालित आवासीय स्कूलों में तिब्बती बच्चों के साथ जोर- जबरदस्ती बंद करने का आह्वान किया। उन्होंने आगे उनसे अस्मिता का दमन करने वाली नीति को बंद करने और पीआरसी से अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत दायित्वों का पालन करने का आह्वान किया।

## ◆ ऑस्ट्रेलियाई सर्वदलीय संसदीय तिब्बत समूह ने विदेश मंत्री पेनी वोंग को पत्र लिखकर चीन पर संयुक्त राष्ट्र की आवधिक समीक्षा में तिब्बत का मुद्दा उठाने का आग्रह किया

tibet.net, २० नवंबर, २०२३

**कैनबरा।** ऑस्ट्रेलियाई सर्वदलीय संसदीय तिब्बत समूह (एएपीजीटी) ने गुरुवार १६ नवंबर को विदेश मंत्री पेनी वोंग को पत्र लिखकर जनवरी २०२४ में चीन पर संयुक्त राष्ट्र की आसन्न आवधिक समीक्षा में चीन-तिब्बत संघर्ष और चीन के भयावह मानवाधिकार रिकॉर्ड को उठाने का आग्रह किया।

एएपीजीटी के सह-अध्यक्षों में सीनेटर डीन स्मिथ, सांसद सुसान टेम्पलमैन और सीनेटर जेनेट राइस शामिल हैं। इन हस्तियों ने विदेश मंत्री से अपील की है कि वे यह सुनिश्चित करें कि चीन की सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा में ऑस्ट्रेलिया की प्रस्तुति में चीनी सरकार द्वारा प्रोत्साहित किए गए 'जातीय अल्पसंख्यक' या 'धार्मिक अल्पसंख्यक' शब्दों के बजाय सीधे तौर पर 'तिब्बत' और 'तिब्बती' जैसे शब्दों का उपयोग हो।

पत्र में तिब्बत में कई मानवाधिकार संबंधी चिंताओं पर ध्यान दिया गया है। इनमें से कुछ हैं- तिब्बती बच्चों पर थोपे गए आवासीय स्कूलों का विशाल नेटवर्क और उन्हें तिब्बती संस्कृति और राष्ट्रीय पहचान से परिचित होने के अवसर से वंचित करना। तिब्बत पर संसदीय समूह ने राजनीतिक रूप से प्रेरित तिब्बतियों के लिए 'व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम' और 'स्वैच्छिक श्रमिक स्थानांरण' के नाम पर जबरन श्रमिक स्थानांतरण कार्यक्रमों के बारे में चिंता व्यक्त की। इसके अलावा, यह ऑस्ट्रेलियाई सरकार से १४वें दलाई लामा के पुनर्जन्म सहित तिब्बती बौद्ध लामाओं के चयन और मान्यता में चीन के कठोर हस्तक्षेप को रोकने की अपील करता है। समूह ने स्वीकार किया है कि ऐसा अधिकार केवल 'तिब्बती लोगों द्वारा अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के अनुसार' निर्धारित किया जाता है। एएपीजीटी के सह-अध्यक्षों ने 'तिब्बती बौद्ध धर्म में जीवित बुद्धों के पुनर्जन्म के प्रबंधन पर उपाय' और '२०१७ के धार्मिक मामलों के विनियम' जैसे चीनी कानूनों को भी अस्वीकार कर दिया।

पत्र का समापन सदस्यों द्वारा यह आशा व्यक्त करते हुए किया गया है कि ऑस्ट्रेलिया यूपीआर प्रक्रिया की अखंडता और ऑस्ट्रेलिया की मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता को बनाए रखने के लिए तिब्बतियों की पीड़ा को लेकर मजबूती से पक्ष रखेगा और चीन के साथ ऑस्ट्रेलिया के व्यापार संबंधों को सुधारने के प्रयास के नाम पर कोई समझौता नहीं करेगा।

## ◆ दिल्ली आईआईएमसी के पत्रकारिता छात्रों ने सीटीए शैक्षणिक दौरा किया

tibet.net, ०६ नवंबर, २०२३

**धर्मशाला।** नई दिल्ली स्थित भारत-तिब्बत समन्वय कार्यालय (आईटीसीओ) ने तिब्बत पर अपने वार्षिक आउटरीच कार्यक्रम के तहत ०३ से ०५ नवंबर २०२३ तक हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तीन दिवसीय शैक्षणिक दौरे का आयोजन किया। कार्यक्रम में भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) और अंग्रेजी पत्रकारिता विभाग, नई दिल्ली के पैंतीस छात्रों और पांच संकाय सदस्यों ने हिस्सा लिया। प्रतिभागियों के साथ आईटीसीओ समन्वयक थुप्टेन रिनज़िन और कार्यक्रम अधिकारी चोनी छेरिंग भी थे।

पूरे कार्यक्रम के दौरान समूह विविध गतिविधियों में लगा रहा। उन्होंने पहले दिन केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) के भ्रमण के साथ अपनी यात्रा की शुरुआत की, जहां उन्होंने सूचना और अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग (डीआईआईआर) के कालोन नोरज़िन डोल्मा से मुलाकात की। सुश्री डोल्मा ने तिब्बत, संगठनात्मक संरचना और सीटीए के कार्यों के बारे में जानकारी प्रदान की। विशेष रूप से अपने विभाग के कार्यों और भूमिका पर प्रकाश डाला। इसके बाद एक प्रश्नोत्तर सत्र में तिब्बत के अंदर की वर्तमान स्थिति, औपनिवेशिक बोर्डिंग स्कूलों और सीटीए की मध्यम-मार्ग नीति पर चर्चा हुई।

समूह ने निर्वासित तिब्बती संसद (टीपीईई) का भी दौरा किया और सांसद तेनज़िन जिगदल के साथ एक जानकारीपूर्ण बातचीत की। जिगदल ने तिब्बती लोकतंत्र के विकास, चुनाव प्रक्रिया और निर्वासित तिब्बती संसद की कार्यप्रणाली और संरचना पर प्रकाश डाला। तिब्बती सांसद एक प्रश्नोत्तर सत्र में भी शामिल हुए, जहां उन्होंने तिब्बती चुनाव प्रक्रिया, निर्वासित तिब्बतियों के चार्टर, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और अन्य विषयों को स्पष्ट किया।

दोपहर में समूह ने सीटीए प्रमुख सिक्योंग पेन्पा छेरिंग से मुलाकात की। उन्होंने छात्रों और संकाय सदस्यों को संबोधित किया, जिसमें तिब्बती पठार के वैश्विक महत्व, इसके भौगोलिक और पर्यावरणीय आयामों पर चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त उन्होंने तिब्बत की राजनीतिक स्थिति, निर्वासित तिब्बती नेतृत्व और ऐतिहासिक भारत-तिब्बत संबंधों से जुड़े विषयों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि तिब्बत और दुनिया के बारे में सूचनाओं से अपडेट रहने के महत्व पर जोर देना मीडिया छात्रों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है। उनके संबोधन के बाद एक चर्चा का सत्र हुआ, जिसके दौरान छात्रों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और तिब्बत के बारे में कई प्रश्न पूछे। सिक्योंग ने सभी सवालों का अपनी वाक्पटुता से जवाब दिया।

इसके अतिरिक्त समूह ने तिब्बती वर्क्स और अभिलेखागार पुस्तकालय (एलटीडब्ल्यूए) का भ्रमण किया, सचिव ल्हावांग के साथ बातचीत की और पुस्तकालय के इतिहास और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी हासिल की।

दूसरे दिन समूह ने तिब्बती चिल्ड्रेंस विलेज (टीसीवी) का दौरा किया और टीसीवी के निदेशक सुल्ट्रिम दोरजी के साथ बातचीत की। यहां समूह ने तिब्बती समुदाय के इतिहास, शिक्षा प्रणाली और टीसीवी के योगदान के बारे में जानकारी हासिल की। इस यात्रा के बाद वे तिब्बती युवा कांग्रेस (टीवाईसी), नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ तिब्बत (एनडीपीटी), और स्टूडेंट्स फॉर फ्री तिब्बत (एसएफटी) सहित प्रमुख तिब्बती गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों से मिले और निर्वासित तिब्बती समुदाय के भीतर उनके संबंधित संगठनों और भूमिकाओं के बारे में जानकारी ली।

समूह ने डीआईआईआर, सीटीए के तिब्बत संग्रहालय का भी दौरा किया, जहां तिब्बती इतिहास में गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त की और नोरबुलिंगका संस्थान के बारे में जानकारी प्राप्त की। तिब्बती लकड़ी की नक्काशी, तैल चित्रकला, थांगका पेंटिंग, गुड़िया संग्रहालय और नोरबुलिंगका मंदिर और दुकान का दौरा करने के साथ ही विभिन्न कलात्मक प्रक्रियाओं का अवलोकन किया।

अंतिम दिन छुगलाखांग मंदिर परिसर, मठों और मैक्लोडगंज और उसके आसपास के अन्य सांस्कृतिक केंद्रों का दौरा शामिल था, जो तिब्बती आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं के बारे में गहन अनुभव प्रदान करता है।

कार्यक्रम का समापन आईटीसीओ समन्वयक थुप्टेन रिनज़िन और कार्यक्रम अधिकारी चोनी छेरिंग को धन्यवाद देने के साथ हुआ और तिब्बत के बारे में ज्ञानवर्धक अवसर प्रदान करने के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया गया। प्रतिभागियों ने अपने मंडलियों और व्यापक भारतीय आबादी के बीच तिब्बत के बारे में जागरुकता बढ़ाने का संकल्प लिया।
अंत में आईटीसीओ समन्वयक थुप्टेन रिनज़िन ने सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया और प्रत्येक सदस्य को खटक (तिब्बती पवित्र सफेद स्कार्फ) प्रदान किया, उनके भविष्य के प्रयासों में सफलता की कामना की और उम्मीद की कि कार्यक्रम ने तिब्बत और तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में उनकी समझ को समृद्ध किया होगा।

## ◆ टीएसजी अरुणाचल प्रदेश ने ताढ़ तारक को नए अध्यक्ष और नीमा सांगे को महासचिव चुना

tibet.net, ०१ नवंबर, २०२३

**ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश)।** अरुणाचल प्रदेश के तिब्बत समर्थक समूह (टीएसजीएपी) ने २७ अक्तूबर, २०२३ को अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में राज्य के पूर्व मंत्री तानयोंग तातक की अध्यक्षता में आयोजित अपनी बैठक में ताढ़ तारक को टीएसजी अरुणाचल प्रदेश का अध्यक्ष और नीमा सांगे को महासचिव के रूप में निर्वाचित किया। साथ ही बैठक में जल्द ही समिति बनाने का निर्णय लिया गया।

२२ अक्तूबर, २०२१ को टीएसजीएपी के तत्कालीन अध्यक्ष गिचो कबाक के असामयिक निधन के बाद से यह पद खाली पड़ा था। कबाक की याद में उपस्थित सामाजिक कार्यकर्ताओं और नगरसेवकों ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए दो मिनट का मौन भी रखा। सांगे और टीएसजीएपी के संस्थापक सदस्य अनोक वांग्सा ने तिब्बत की स्थिति, तिब्बती मुद्दों पर प्रकाश डाला और अपने विभिन्न मुद्दों को तिब्बत समर्थक समूहों के राष्ट्रीय छतरी निकाय-कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज-इंडिया (सीजीटीसी-आई) में इसके राष्ट्रीय संयोजक आऱ क़े खिरमे के परामर्श से उठाने पर जोर दिया।

टीएसजीएपी की विज्ञप्ति के अनुसार, तारक ने अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए टीम भावना के साथ संगठन का नेतृत्व करने का आश्वासन दिया और तिब्बत मुद्दे को हल करने के लिए केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) के मध्यम मार्ग दृष्टिकोण का समर्थन किया।

भारत भर में फैले विभिन्न टीएसजी तिब्बत की आजादी के लिए काम करते हैं। कम्युनिस्ट चीन ने १९५९ में तिब्बती राष्ट्रीय जनक्रांति का दमन कर अवैध रूप से तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। तिब्बत के आध्यात्मिक धर्मगुरु और तत्कालीन राजनीतिक नेता परम पावन १४वें दलाई लामा हजारों तिब्बतियों के साथ अरुणाचल प्रदेश के रास्ते भारत पलायन कर गए और १९६० के दशक में उन्होंने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की स्थापना की।

तिब्बत की अधिकांश भूमि को लेकर चीन द्वारा आधिकारिक तौर पर १९६५ में तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र गठित किया गया। इसमें तिब्बत के यू-छांग, खाम और अमदो प्रांतों के सभी क्षेत्र शामिल हैं।

इसके बाद से दुनिया भर के तिब्बती परम पावन १४वें दलाई लामा के नेतृत्व में सभी तिब्बतियों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि परम पावन सम्मानजनक रूप से तिब्बत लौट सकें। इस पूरी लड़ाई में दुनिया भर के तिब्बतियों का प्रतिनिधित्व विभिन्न तिब्बत समर्थक समूह कर रहे हैं।

## ◆ 'तिब्बत मुक्त करो, भारत बचाओ' के उद्घोष के साथ पांचवीं जनजागरण साइकिल यात्रा पश्चिम बंगाल के कोलकाता से शुरू

tibet.net, १० नवंबर, २०२३

**नई दिल्ली।** तिब्बत के लंबे समय से मित्र संदेश मेश्राम उर्फ समतेन येशी वर्तमान में कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज़- इंडिया (सीजीटीसी-आई) के क्षेत्रीय संयोजकों में से एक के रूप में कार्यरत हैं और भारत-तिब्बत मैत्री संघ (आईटीएफएस) के सदस्य भी हैं। नागपुर में रहनेवाले श्री मेश्राम ने ने 'फ्री तिब्बत, सेव इंडिया (तिब्बत मुक्त करो, भारत बचाओ)' संदेश के साथ पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से ०५ नवंबर, २०२३ को अपनी पांचवीं जनजागरण साइकिल यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा में तिब्बती पर्यावरणविद् और परोपकारी कर्मा समद्रूप की रिहाई के लिए अभियान भी शामिल है।

यात्रा का शुभारंभ कार्यक्रम कोलकाता के बौद्ध मठ में आयोजित किया गया था, जिसमें तिब्बत समर्थक और पूर्व सीजीटीसी-आई सदस्य एडवोकेट रूबी मुखर्जी भी शामिल हुई थीं। शामिल लोगों में स्थानीय भारतीय समर्थक और कोलकाता में तिब्बती समुदाय के सदस्य, जिनमें तिब्बती स्वेटर विक्रेता संघ के सदस्य भी शामिल हैं। संदेश मेश्राम ने सदस्यों को अपनी जनजागरण साइकिल यात्रा और तिब्बत के हित के लिए इसके महत्व के बारे में जानकारी दी। भगवान बुद्ध का आशीर्वाद लेते हुए उन्होंने अपनी जनजागरण साइकिल यात्रा शुरू की। इसके पहले सदस्यों ने उन्हें खटक भेंट की और कृतज्ञता ज्ञापन के साथ उनका स्वागत किया और उनके अच्छे स्वास्थ्य और सफल यात्रा के लिए शुभकामनाएं दीं।

पांचवीं जनजागरण साइकिल यात्रा पश्चिम बंगाल के कोलकाता से शुरू होकर पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के शहरों और कस्बों से लगभग २५०० किलोमीटर की दूरी तय करते हुए राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में १० दिसंबर, २०२३ को समाप्त होगी।

साइकिल यात्रा का मुख्य उद्देश्य तिब्बत और कम्युनिस्ट चीनी शासन की दमनकारी नीतियों के तहत तिब्बत के अंदर व्याप्त गंभीर स्थिति के बारे में आम भारतीय जनता के बीच जागरुकता पैदा करना है। यह साइकिल यात्रा तिब्बती पर्यावरणविद् और परोपकारी कर्मा समद्रुप की रिहाई के लिए भी अभियान चला रही है, जिन्हें चीनी अधिकारियों ने झूठे आरोपों में १५ साल जेल की सजा सुनाई है। अभियान में उन सभी तिब्बती राजनीतिक कैदियों की रिहाई का भी आह्वान किया गया है जिन्हें झूठी सजा सुनाई गई है और जेलों में प्रताड़ित किया जा रहा है।

इससे पहले श्री मेश्राम इस तरह की चार साइकिल यात्राएं आयोजित कर चुके हैं। पहली साइकिल यात्रा २०१४ में नागपुर से 'तिब्बत बचाओ साइकिल अभियान' शीर्षक से हुई थी। इस यात्रा में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों से गुजरते हुए ४००० किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। इसके बाद २०१६ में उनकी दूसरी साइकिल यात्रा 'तिब्बत को बचाने के लिए साइकिल रैली' शीर्षक से नागपुर से शुरू हुई, जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से १२०० किलोमीटर की दूरी तय करते हुए गुजरी और बिहार के बोधगया पहुंची।

तीसरी साइकिल यात्रा २०१७ में २० अक्तूबर को बोधगया से चीन-भारत युद्ध को यादगार बनाने के लिए सिक्किम के नाथू-ला दर्रा तक १२७० किलोमीटर तक हुई थी। यात्रा के बीच में उनकी स्वास्थ्य समस्या के कारण चौथी साइकिल यात्रा दो चरणों में करनी पड़ी। पहले चरण में दिसंबर २०१९ से फरवरी २०२० तक हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से कर्नाटक के मुंडगोड तक लगभग ७५०० किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। दूसरा चरण कर्नाटक के मुंडगोड से कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु तक १० दिसंबर २०२१ से १० जनवरी, २०२२ तक लगभग २००० किलोमीटर की दूरी तय करते हुए संपन्न हुआ था। यह यात्रा उत्तर कन्नड, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के प्रमुख शहरों, कस्बों और गांवों से होकर गुजरा था।

इस रिपोर्ट को लिखने तक संदेश मेश्राम ने पश्चिम बंगाल के खड़गपुर और नयाग्राम और झारखंड के जमशेदपुर और बुंडू में रुकते हुए पांच दिनों में ९२ किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी।

## ◆ जापान, तिब्बत, उग्यूर और दक्षिणी मंगोलिया ने चीन के कुख्यात धार्मिक आदेश संख्या- १९ की निंदा में सेमिनार आयोजित किया

tibet.net, २० नवंबर, २०२३

**टोक्यो।** सेव तिब्बत नेटवर्क और तिब्बत हाउस जापान ने चीन द्वारा ०१ सितंबर को धार्मिक आदेश संख्या-१९ जारी करने के खिलाफ २० नवंबर, २०२३ को टोक्यो स्थित शिंजुकु ऐतिहासिक संग्रहालय में एक सेमिनार का आयोजन किया। सेमिनार के पैनलिस्टों में जापानी सांसद मित्सुबायाशी हिरोमी, डॉ. मियावाकी जुंको, सुपर संघ के उपाध्यक्ष रेव्ह कोबायाशी शुई और डॉ. दक्षिण मंगोलियाई कांग्रेस के महासचिव गोवरुद अर्चा, जापान-उग्यूर एसोसिएशन के सावत मोहम्मद और परम पावन दलाई लामा के संपर्क कार्यालय के डॉ. आर्य छेवांग ग्यालपो थे। सभी पैनलिस्टों ने इस आदेश की

भयानक प्रकृति पर बात की।

प्रतिभागियों ने सीसीपी शासन द्वारा चीन और उसके कब्जे वाले क्षेत्रों में धार्मिक गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के लिए जारी धार्मिक आदेश का मूल्यांकन किया। उन्होंने चीन की देशभक्ति शिक्षा नीति पर भी बात की जो बच्चों को चीनी कम्युनिस्ट विचारधारा और झूठे प्रचार के लिए मजबूर कर राजी करने के लिए बनाई गई है। उन्होंने कहा कि यह धार्मिक व्यवस्था इस बात का चरम उदाहरण है कि एक तानाशाही शासन लोगों से उनके धर्मों के बारे में सोचने और उनका पालन करने की स्वतंत्रता कैसे छीन लेती है।

विधायक मित्सुबायाशी हिरोमी ने पूर्वी तुर्केस्तान में काम करने के अपने अनुभव के बारे में बात की और खुशी व्यक्त की कि तिब्बती, उग्यूर और दक्षिणी मंगोलियाई लोग चीनी और कब्जे वाले क्षेत्रों के लोगों के दिल और दिमाग को नियंत्रित करने की सीसीपी की इस कुख्यात नीति पर चर्चा करने के लिए एक साथ आए हैं। उन्होंने कहा कि चीन के मानवाधिकार उल्लंघनों की निगरानी के लिए जापान संसदीय समूह और उग्यूर संसदीय समर्थक समूह के महासचिव के रूप में वह यह सुनिश्चित करेंगे कि जापानी सांसदों द्वारा इस घृणित नीति की निंदा की जाए।

दक्षिण मंगोलिया कुरिलताई और जापान-उग्यूर एसोसिएशन के डॉ. गोवरुद अर्चा और सावुत मुहम्मद ने सीसीपी के नियंत्रण वाले अपने-अपने गृहक्षेत्रों में हो रहे धार्मिक अत्याचारों और शिक्षा-प्रचार पर बात की और बताया कि कैसे यह नई क्रूर नीति लोगों के जीवन और धार्मिक स्वतंत्रता को बहुत प्रभावित करनेवाली है।

तिब्बती मुद्दों का समर्थन करने वाले जापानी भिक्षुओं और आम लोगों के संघ-सुपर संघ- के भिक्षु कोबायाशी शुई ने पुनर्जन्म की महत्वपूर्ण अवधारणा के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि कैसे तिब्बती बौद्ध धर्म के मूल में अभी भी यह अवधारणा है और कैसे नास्तिक देश चीन इस पवित्र धार्मिक अवधारणा में हस्तक्षेप कर रहा है। डॉ. मंगोलियाई और चीनी इतिहासकार मियावाकी जुंको ने इस ऐतिहासिक पहलू के बारे में बात की कि चीन क्या है और कैसे सीसीपी मंगोलियाई युआन राजवंश और मांचू किंग राजवंश पर दावा करने की कोशिश कर रही है।

परम पावन दलाई लामा के संपर्क कार्यालय के प्रतिनिधि डॉ. आर्य छेवांग ग्याल्पो ने सेमिनार में भाग लेने के लिए वक्ताओं, अतिथियों, प्रतिभागियों और मीडिया को धन्यवाद दिया। उन्होंने प्रतिभागियों को बताया कि चीन विभिन्न संदिग्ध तरीकों से चीन और अन्य कब्जे वाले क्षेत्रों में धार्मिक स्वतंत्रता का अपहरण कर रहा है। लेकिन इस कुख्यात धार्मिक आदेश संख्या- १९ के माध्यम से चीन बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम और ताओवाद की धार्मिक शिक्षाओं में धार्मिक हस्तक्षेप को वैध बनाने और कम्युनिस्ट विचारधारा को लागू करने की कोशिश कर रहा है।

प्रश्नोत्तर सत्र के बाद श्री माकिनो सेशू ने कार्यक्रम का समापन किया और कार्यवाही का सारांश प्रस्तुत किया। सेमिनार का प्रस्ताव इस प्रकार घोषित किया गया, 'हमने सेमिनार से सीखा है कि चीनी धार्मिक आदेश संख्या-१९ न केवल चीन और चीन के कब्जे वाले क्षेत्रों में धार्मिक साधकों के लिए बल्कि पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए भयानक और हानिकारक है। इसलिए, इस सेमिनार के आयोजक और प्रतिभागी चीन के धार्मिक आदेश संख्या- १९ की निंदा करते हैं और चीनी नेतृत्व से इस निंदनीय आदेश को तुरंत वापस लेने का आग्रह करते हैं। हम जापानी जनता और दुनिया भर के मंदिरों, चर्चों, मस्जिदों और अन्य धार्मिक संस्थानों से अनुरोध करते हैं कि वे सीसीपी की विचारधारा के साथ धार्मिक शिक्षण को अपवित्र करने के सीसीपी के इस प्रयास का विरोध करें। हम चीनी सरकार से लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप बंद करने का आग्रह करते हैं।'

सेव तिब्बत नेटवर्क के अन्नी किताजावा ने कार्यक्रम का संचालन किया। अल्पसंख्यक नागरिकों की प्रतिनिधि समिति ने इस आयोजन का समर्थन किया और अपने फेसबुक के माध्यम से सेमिनार के लाइव प्रसारण की व्यवस्था की। आयोजन निःशुल्क था, लेकिन कुछ लोगों ने खर्च वहन करने के लिए दान की पेशकश की।

## ◆ अरुणाचल प्रदेश के तिब्बत समर्थक समूह ने ईटानगर में कार्यकारी निकाय की बैठक आयोजित की

tibet.net, २२ नवंबर, २०२३

**नई दिल्ली।** अरुणाचल प्रदेश के तिब्बत समर्थक समूह (टीएसजीएपी) की कार्यकारी निकाय बैठक १९ नवंबर २०२३ को ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश के तिब्बत समर्थक समूह के अध्यक्ष श्री ताढ़ तारक की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

बैठक में कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज़- इंडिया (सीजीटीसी-आई) के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व सांसद श्री आर.के. खिरमे, तिब्बती कार्यकर्ता और लेखक श्री तेनज़िन त्सुन्दुए, राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष और ईटानगर बौद्ध संस्कृति सोसायटी (आईबीसीएस) के अध्यक्ष डॉ. लीकी वांगचुक, मोन मिमांग छोकपा (मोनपास के सीबीओ) के अध्यक्ष श्री दोरजी फुंटसो, टुटिंग मेम्बा वेलफेयर सोसाइटी (मेम्बा समुदाय के सीबीओ) के अध्यक्ष इंजी. पेमा दोरजी खोची, पूर्व मंत्री एवं राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति के अध्यक्ष श्री अनोक वांगसा, अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री संबू सियोंग्जू के अलावा टीएसजीएपी के नए कार्यकारी सदस्यों और शुभचिंतकों ने भाग लिया।

विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज-इंडिया के राष्ट्रीय संयोजक श्री आर.के. खिरमे ने राज्य भाजपा उपाध्यक्ष श्री ताढ् तारक की अध्यक्षता में टीएसजीएपी की एक नई टीम के गठन की सराहना की। साथ ही उन्होंने अपनी टिप्पणी में तिब्बत-चीन संघर्ष को उजागर करते हुए कहा, 'कुछ संगठन और समूह तिब्बत के लिए आजादी की मांग कर रहे हैं और कुछ पीआरसी से स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। हम एक कार्यकर्ता के रूप में तिब्बत का समाधान चाहते हैं।' उन्होंने आगे कहा, 'परम पावन १४वें दलाई लामा भारत सरकार के सबसे लंबे समय तक मेहमान हैं और तिब्बती शरणार्थी भी। उन्होंने भारत में कभी भी एक इंच भूमि का अतिक्रमण नहीं किया और स्वतंत्रता के लिए अपना संघर्ष जारी रखने के लिए भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से परहेज किया। इसलिए, श्री खिरमे ने तिब्बत की आजादी के प्रयासों के

समर्थन में भारतीयों की आवाज की क्षमता को रेखांकित करते हुए युवा पीढ़ी के बीच तिब्बती संघर्ष के बारे में जागरुकता पैदा करने पर जोर दिया।' उन्होंने कोई वैध अधिकार न होने के बावजूद परम पावन १४वें दलाई लामा के पुनर्जन्म को मान्यता देने के अधिकार को हथियाने के चीनी नास्तिक सरकार के प्रयास की भी निंदा की।

टीएसजीएपी के अध्यक्ष श्री ताढ़ तारक ने तिब्बत सीमाओं की अपनी हालिया यात्रा और सीमा क्षेत्र के लोगों के साथ बातचीत के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा ने उन्हें तिब्बती मुद्दे का समर्थन करने के लिए प्रेरित किया और अरुणाचल के लोगों द्वारा तिब्बतियों के साथ साझा किए जाने वाले भावनात्मक संबंध के बारे में बताया।

श्री तारक ने टीम की ताकत में गहरी आशा के साथ, गणमान्य व्यक्तियों से सर्वोत्तम प्रयास के साथ तिब्बती स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन करने का आग्रह किया और कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज़- इंडिया के निर्देश के अनुसार काम करने का आश्वासन दिया। उन्होंने टीम भावना और टीम शक्ति के साथ देश में सर्वांगीण विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पेमा खांडू की भी सराहना की।

पूर्व मंत्री और एसएलएमसी के अध्यक्ष और टीएसजीएपी के संस्थापक सदस्य श्री अनोक वांगसा ने नई टीम को बधाई संदेश दिया और तिब्बती मुद्दे और तिब्बत के मुद्दों पर प्रकाश डाला, जिसमें कहा गया कि, 'तिब्बती शरणार्थियों की तुलना राज्य में चकमा-हाजोंग शरणार्थियों से नहीं की जा सकती है।' उन्होंने नई टीम को तिब्बतियों और तिब्बती मुद्दों के बारे में जागरुकता से अवगत कराया ताकि ऐसे मुद्दों को किसी भी स्तर पर किसी भी मंच पर आगे बढ़ाया जा सके और समर्थन किया जा सके।

तिब्बती कार्यकर्ता-सह-लेखक तेनज़िन त्सुंडु ने टीएसजीएपी की कार्यकारी निकाय की बैठक में अपने संबोधन में मानवता, विशेष रूप से दुनिया भर में पीड़ित तिब्बतियों की मदद में टीएसजी के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने तिब्बत मुक्ति साधना पर प्रकाश डालते हुए तिब्बत की ऐतिहासिक आजादी पर जोर दिया। उन्होंने घोषणा की कि कब्जे वाली भूमि से तिब्बत की यथास्थिति में परिवर्तन आवश्यक था। उन्होंने आशा व्यक्त की कि तिब्बती स्वतंत्रता प्रयास पीआरसी से स्वतंत्रता सुनिश्चित कराएगा और इसके लिए तिब्बतियों को संघर्ष का नेतृत्व करना चाहिए। तिब्बत समर्थक समूहों के आंदोलन के समर्थन से तिब्बतियों को वांछित परिवर्तन के लिए संघर्ष तेज करना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा, 'तिब्बत की आजादी, भारत की सुरक्षा और तिब्बती मुद्दे के लिए समर्थन को दया के बजाय भारतीय और तिब्बती समृद्धि दोनों की ओर निर्देशित करने की आवश्यकता है।

टीएसजीएपी के महासचिव श्री नीमा सांगेय ने टीएसजीएपी के गठन के मुख्य उद्देश्य पर प्रकाश डाला, जो मानवीय आधार पर तिब्बती मुद्दे का समर्थन करना है। उन्होंने कहा कि तिब्बत और उसके संघर्षों और तिब्बती मुद्दों को भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानना, समय की मांग है। उन्होंने २०१८ में एक साल तक चले 'थैंक यू इंडिया' अभियान के लिए केंद्रीय तिब्बती प्रशासन द्वारा शुरू की गई गतिविधियों पर भी विचार-विमर्श किया, जो परम पावन दलाई लामा के निर्वासित होकर भारत में कदम रखने के ६०वें वर्ष का प्रतीक है। २०१८ के इन कार्यक्रमों में पद यात्रा (शांति मार्च), धन्यवाद भारत सार्वजनिक कार्यक्रम, तिब्बत उत्सव, भारत के लिए प्रार्थना, हरित भारत की ओर, स्वस्थ भारत की ओर, भूखों को खाना खिलाना, स्वच्छ भारत की ओर, ठंड को कवर करना आदि शामिल हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि तिब्बतियों ने तिब्बती मुक्ति साधना को 'मेड इन इंडिया' कहा और इसकी सफलता भारत की सफलता की कहानी होगी। उन्होंने सभी सदस्यों से आगे आने और तिब्बती मुक्ति साधना का समर्थन करने का आह्वान करते हुए कहा, 'हमारे समर्थन से तिब्बती मुद्दे से निश्चित रूप से तिब्बती नेताओं का लड़ाई में मनोबल बढ़ेगा।' उन्होंने अंत में कहा कि टीएसजीएपी परम पावन दलाई लामा के लंबे जीवन, तिब्बत-चीन संघर्ष का त्वरित समाधान और परम पावन और निर्वासित तिब्बती लोगों की उनकी मातृभूमि में वापसी के लिए प्रार्थना करता है।

टीएसजीएपी में ४० नए कार्यकारी सदस्य शामिल हैं। इनमें अध्यक्ष श्री ताढ़ तारक, महासचिव श्री नीमा सांगेय, सलाहकार, उपाध्यक्ष, सचिव, सहायक सचिव, समन्वयक, सह-समन्वयक, संयोजक, सह-संयोजक, मीडिया सलाहकार और कानूनी सलाहकार शामिल हैं। सदस्यों का चयन राज्य की प्रमुख हस्तियों, जैसे पूर्व मंत्रियों, पूर्व विधायकों, नगरसेवकों (आईएमसी ईटानगर), पूर्व पंचायत नेताओं और सरकारी अधिकारियों में से किया गया था। इन सबकों नियुक्ति पत्र श्री आर.के. खिरमे और श्री ताढ़ तारक द्वारा गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में सौंपा गया।

इसके अलावा, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन लद्दाख और साबू सोलिटेरियन गेस्ट हाउस, संग्रहालय और पुस्तकालय के निदेशक न्गावांग छेरिंग शक्सपो, टीएसजीएपी के संयोजक श्री ताढ़ टैगो, ईटानगर नगर निगम (आईएमसी) की पार्षद श्रीमती ताड़र हांघी और टीएसजीएपी के उपाध्यक्ष ने भी इस अवसर को संबोधित किया।

बैठक के दौरान सदस्यों ने आत्मदाह करने वाले तिब्बतियों को श्रद्धांजलि देने के लिए दो मिनट का मौन रखा।

## ◆ तिब्बत पर्यावरण सम्मेलन में प्रतिनिधियों ने नदी की चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक प्रयास की शपथ ली

tibet.net, २९ नवंबर, २०२३

तिब्बत नीति संस्थान द्वारा आयोजित और सामाजिक अनुसंधान संस्थान, चुलालोंगकोर्न विश्वविद्यालय द्वारा सह-मेजबानी किए गए तिब्बत पर्यावरण सम्मेलन में विभिन्न दक्षिण -पूर्व एशियाई देशों के सात प्रतिष्ठित वक्ताओं ने तीन अलग-अलग पैनलों में चर्चा की।

विभिन्न पैनलों में वक्ताओं ने हिमालयी समुदायों में जलवायु लचीलेपन के पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करने से लेकर दक्षिण-पूर्व एशिया में ग्रीष्मकालीन मानसून की शुरुआत पर तिब्बती पठार के प्रभाव तक पठार के पारिस्थितिकीय महत्व और वैश्विक जलवायु वार्ताओं में तिब्बत की जरूरतों और जनभागीदारी

के महत्व पर प्रकाश डाला।

२८ नवंबर को समापन सत्र में चुलालोंगकोर्न विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज के पूर्व निदेशक प्रोफेसर सुरीचाई वुन गियो का संबोधन हुआ। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज जिस पानी के मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है, इसके लिए एक देश जिम्मेदार नहीं हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नदियों को बचाने के लिए एकजुट होकर चुनौतियों से पार पाना सभी देशों की जिम्मेदारी है।

सोशल रिसर्च इंस्टीट्यूट के डॉ. सुरंगरुत जुमनियानपोल ने थाईलैंड और मेकांग नदी का उदाहरण दिया और निचले देशों की ओर अत्यधिक खनन से तिब्बती पठार में उत्पन्न हुए इसके निहितार्थ पर प्रकाश डाला।

डॉ. छेवांग ग्याल्पो आर्य ने तर्क दिया कि यह सम्मेलन सभी दक्षिण-पूर्व और एशियाई देशों के लिए भविष्य की नदी सुरक्षा के लिए मिलकर काम करने का एहसास कराता है। उन्होंने वक्ताओं और आयोजकों को सराहना के प्रतीक बांटे। टीपीआई के शोधार्थी डेचेन पाल्मो ने धन्यवाद ज्ञापन दिया।

## ◆ भारत-तिब्बत समन्वय कार्यालय ने गुवाहाटी में तिब्बत समर्थक समूहों के साथ बैठक की

tibet.net, २५ नवंबर, २०२३

**गुवाहाटी।** भारत-तिब्बत समन्वय कार्यालय (आईटीसीओ) ने २५ नवंबर २०२३ को असम की राजधानी गुवाहाटी में तिब्बत समर्थक समूहों के साथ बैठक की। इसका उद्देश्य तिब्बत समर्थक समूहों के साथ समन्वय बढ़ाना, तिब्बत समर्थक समूहों के बीच अधिक सामूहिक सहयोग और जुड़ाव लाना और सातवें अखिल भारतीय तिब्बत समर्थक समूह सम्मेलन में पारित कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज़- इंडिया (सीजीटीसी-आई) की कार्रवाई योजना का पालन करना था।

अनुरोध करने पर तिब्बती सांसदों- खेंपो जम्फाल तेनज़िन और सांसद फुरपा दोरजी ग्यालधोंग ने शिलांग स्थित तिब्बती सेटलमेंट अधिकारी तेनज़िन सैमटेन के साथ कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। दोनों सांसद पूर्वोत्तर भारत की आधिकारिक यात्रा के सिलसिले में शहर में थे।

माननीय सांसदों ने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन और उसकी नीति, मध्यम मार्ग दृष्टिकोण, तिब्बती संघर्ष की वर्तमान स्थिति और स्थिति पर व्यापक रूप से प्रकाश डाला। उन्होंने भारत सरकार और तिब्बत समर्थक समूहों के अटूट समर्थन के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया। साथ ही तिब्बत के मुद्दे के समाधान के लिए निरंतर समर्थन और सहयोग की अपील की। अंत में एक प्रश्नोत्तर वाला आपसी चर्चा का सत्र आयोजित किया गया।

आईटीसीओ, नई दिल्ली का प्रतिनिधित्व करने वाली ताशी डेकी ने प्रतिभागियों का गर्मजोशी से स्वागत किया और इसके उद्देश्य पर प्रकाश डालने के साथ बैठक की शुरुआत की। उन्होंने सदियों से भारत-तिब्बत संबंधों, स्वतंत्र तिब्बत के बारे में तथ्य, निर्वासित तिब्बती और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन, तिब्बत में वर्तमान स्थिति और तिब्बत भारत के लिए क्यों मायने रखता है जैसे मुद्दों पर पीपीटी प्रदान की। इसके अलावा, सातवें अखिल भारतीय तिब्बत समर्थक समूह सम्मेलन की घोषणा और कार्य योजनाएं प्रस्तुत की गईं और स्कूलों, विश्वविद्यालयों में तिब्बत के पक्ष में कार्यक्रमों को मजबूत करने के तरीकों पर आकर्षक चर्चा की गई और थिंक टैंक के साथ गोलमेज वार्ता की गई।

बैठक के दौरान गुवाहाटी में तिब्बत समर्थक समूहों के अतीत के साथ-साथ वर्तमान कार्यक्रमों की समीक्षा और सातवें अखिल भारतीय तिब्बत समर्थक समूह सम्मेलन की कार्ययोजना और घोषणा के अनुरूप आगामी गतिविधियों/कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। टीएसजी सदस्यों ने भारत के साथ-साथ विश्व स्तर पर तिब्बती आंदोलन को तेज करने और सुरक्षित करने के लिए फीडबैक और अपने सुझाव प्रदान किए।

गुवाहाटी के टीएसजी उदार थे और उन्होंने आईटीसीओ द्वारा आयोजित कार्यक्रम की सराहना की और तिब्बत के पक्ष में कार्यक्रम और जन जागरुकता को प्रभावी ढंग से प्रोत्साहित करने के लिए अधिक व्यावहारिक कार्यक्रमों के लिए आवाज उठाई।

बैठक में भारत-तिब्बत संघ, भारत तिब्बत समन्वय संघ, भारत-तिब्बत सहयोग मंच के १० से अधिक सदस्यों और कुछ व्यक्तिगत तिब्बत समर्थकों ने भाग लिया।

## ◆ भारत- तिब्बत सहयोग मंच के असम प्रांत ने १२वीं तवांग तीर्थ यात्रा का आयोजन किया

tibet.net,२४ नवंबर, २०२३

**गुवाहाटी।** भारत-तिब्बत सहयोग मंच (बीटीएसएम) के असम प्रांत द्वारा २४ नवंबर २०२३ को दिसपुर के पीडब्ल्यूडी कन्वेंशन हॉल में १२वीं तवांग तीर्थ यात्रा- २०२३ का उद्घाटन समारोह सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इसे २५ नवंबर २०२३ को बीटीएसएम के संरक्षक और वरिष्ठ आरएसएस प्रचारक माननीय श्री इंद्रेश कुमार के आशीर्वाद और मार्गदर्शन में असम की राजधानी गुवाहाटी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यात्रियों ने बड़े उत्साह और समर्पण के साथ २५ से ३० नवंबर २०२३ तक एक सप्ताह की लंबी यात्रा शुरू की।

उद्घाटन समारोह में भाजपा असम के संगठन मंत्री श्री रवीन्द्र राजू, जीएमसी गुवाहाटी के मेयर श्री मृगेन सरानिया, प्रलाशबाड़ी के विधायक श्री हेमंगा ठाकुरिया, बीटीएसएम असम प्रांत के अध्यक्ष श्री कैलाश शर्मा, बीटीएसएम के राष्ट्रीय महासचिव श्री पंकज गोयल, नागांव के पूर्व सांसद श्री राजेन गोहेन, श्री रिनचेन खांडो खिरमें (पूर्व सांसद और मंत्री, अरुणाचल प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय संयोजक, सीजीटीसी-आई) और शिलांग-मेघालय के तिब्बती सेटलमेंट अधिकारी तेनज़िन समतेन का गर्मजोशी से स्वागत किया गया और उन्होंने समारोह की अध्यक्षता की।

देश के विभिन्न राज्यों से आए लगभग २५० तवांग तीर्थ यात्री असम के गुवाहाटी से मोंगलदाई और रोवटा होते हुए बलेमू (जिसे टिन अली के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहां असम, अरुणाचल प्रदेश और पड़ोसी देश भूटान की भौगोलिक सीमाएं मिलती हैं) के रास्ते यात्रा करेंगे। यात्री बोमडिला, दिरांग, सेला पास, जावंतगढ़ से बलेमू होते हुए तवांग पहुंचेंगे।

तवांग पहुंचने पर यात्री प्रसिद्ध तवांग मठ के दर्शन करेंगे और वहां से अपनी आगे की यात्रा के लिए आशीर्वाद लेंगे। अगले दिन वे बुमला में भारत-तिब्बत सीमा का दौरा करेंगे। उन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर भारतीय सेना को श्रद्धाजलि और नमन अर्पित किया। वे भारत मां की क्षेत्रीय अखंडता के लिए धरती पूजन करेंगे। अपनी वापसी यात्रा में यात्री संगेसर त्सो का दौरा करेंगे जो लोकप्रिय रूप से माधुरी झील और जंग वॉटर फॉल्स के नाम से जाना जाता है और अंत में यात्रा का समापन असम के गुवाहाटी में होगा।

यात्री ३० नवंबर २०२३ को तेजपुर पहुंचेंगे और तेजपुर के माननीय विधायक श्री पृथ्वीराज राभा, बीटीएसएम असम के सलाहकार और बीटीएसएम तेजपुर के सीमा मेच प्रभारी श्री अरूप बारठाकुर द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। १२वीं तवांग तीर्थ यात्रा का समापन समारोह भारत- तिब्बत सहयोग मंच के राष्ट्रीय महासचिव श्री पंकज गोयल के नेतृत्व में तेजपुर में आयोजित किया जाएगा। जैसा कि श्री पंकज ने व्यक्त किया और कहा, '१२वीं तवांग तीर्थयात्रा तिब्बत केमुददे्त होगी।' साथ ही चीन और दुनिया को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) द्वारा तिब्बत पर अवैध कब्जे की कड़ी निंदा करने, पंचशील समझौते का अनादर करने और तिब्बत में तिब्बती लोगों के साथ हो रहे अन्याय पर प्रकाश डालने की अपील करने का संदेश भेजेंगे। इस अवसर पर भूमला सीमा पर 'चीन हाय-हाय' और 'चीन वापस जाओ' जैसे असहमति जताने वाले नारे गूंजे।

## ◆ जैसे ही तिब्बत जिजांग बना कि दिल्ली को एक नई समस्या का सामना करना पड़ेगा

Deccanchronicle.com, २२ नवंबर, २०२३

कम्युनिस्ट चीन अक्सर लोगों, स्थानों और यहां तक कि राष्ट्रों के नाम भी बदल देता है। नया मामला तिब्बत का है, जिसे अब ज़िज़ांग नाम दिया गया है।

धरती के दो सबसे शक्तिशाली देशों के नेताओं के बीच लंबे समय से प्रतीक्षित बैठक आखिरकार १५ नवंबर को सैन फ्रांसिस्को के बाहरी इलाके में एक फार्महाउस में हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने कहा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग प्रभावी 'तानाशाह' है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि बैठक से जो कुछ भी अच्छा हो सकता था, वह हुआ। जब उनसे पूछा गया कि क्या उनका अब भी मानना है (जून २०२३ की बात है) कि श्री शी तानाशाह है, श्री बिडेन ने उत्तर दिया, 'देखिए, ऐसा ही हैं। वह इस अर्थ में तानाशाह हैं कि वह एक ऐसे देश को चलाते हैं जो कम्युनिस्ट विचारधारा पर चलने वाला देश है। उस देश देश की शासन प्रणाली ऐसी है जो हमारी सरकार से बिल्कुल भिन्न स्वरूप पर आधारित है।'अपने राष्ट्रपति की बात सुनकर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मुस्कुराते हुए कहा, 'उन्होंने इसे फिर साबित किया है।'चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने इस पर प्रतिक्रिया देने में देर नहीं की। उन्होंने अगले ही दिन १६ नवंबर गुरुवार को नियमित प्रेस ब्रीफिंग में संवाददाताओं से कहा, यह बयान गलत और बेहद गैर-जिम्मेदाराना राजनीतिक जुमलेबाजी है। लेकिन रात्रि में हुए स्वागत भोज में श्री शी का भाषण बिल्कुल निर्विवाद रहा। उन्होंने बेल्ट एंड रोड पहल के साथ-साथ वैश्विक विकास पहल (जीडीआई), वैश्विक सुरक्षा पहल (जीएसआई) और वैश्विक सभ्यता पहल (जीसीआई) पर बात की। साथ ही उन्होंने प्रस्ताव दिया कि चीन 'हर समय अमेरिका सहित सभी देशों के लिए खुला है। चीन अमेरिका द्वारा प्रस्तावित बहुपक्षीय सहयोग पहल में भाग लेने के लिए भी तैयार है।

'उन्होंने अमेरिका की अपनी पहली यात्रा को याद करते हुए कहा, 'मैं आयोवा में ड्वोरचक्स में रुका था। मुझे अभी भी उसका पता याद है - २९११ बोनी ड्राइव। मैंने वहां के लोगों के साथ जो दिन बिताए वे अविस्मरणीय हैं। मेरे लिए वे अमेरिका का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे दो देशों के लोग बड़े दयालु, मिलनसार, मेहनती और जमीन से जुड़े हुए हैं।'ये विकट प्रतीत होने वाले मतभेदों से निपटने के अलग तरह के उपाय हैं।लेकिन क्या महाबलीपुरम याद है? उस समय २०१९ में मोदी-शी मुलाकात की सभी ने तारीफ की थी। लेकिन सात महीने बाद ही क्या हुआ था? पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पूर्वी लद्दाख में घुस गई थी।

हालांकि, कैलिफ़ोर्निया मुलाकात की समाप्ति पर एक नए टकराव की शुरुआत हो सकती है (ताइवान या दक्षिण चीन सागर में?)। लेकिन किसी को भी वर्तमान में चीन में कठिन जीवन की वास्तविकताओं को नहीं भूलना चाहिए, विशेष रूप से जिसे बीजिंग 'अल्पसंख्यक क्षेत्र' कहता है। मतलब तिब्बत और झिंझियांग। १० नवंबर को सिन्हुआ ने बताया कि रास्ट्रीय सूचना कार्यालय परिषद (स्टेट काउंसिल इंफॉर्मेशन ऑफिस) ने ज़िज़ांग स्वायत्त क्षेत्र के शासन को लेकर श्वेत-पत्र जारी किया था।

**यह ज़िज़ांग क्या है?**

एक असली साम्राज्यवादी शक्ति का चरित्र दिखाते हुए कम्युनिस्ट चीन अक्सर लोगों, स्थानों और यहाँ तक कि राष्ट्रों के नाम भी बदल देता है। प्रस्तुत मामला तिब्बत का है, जिसे अब 'ज़िज़ांग' कहा जा रहा है।

श्वेत-पत्र का शीर्षक है- 'नए युग में ज़िज़ांग के शासन पर सीपीसी नीतियां: दृष्टिकोण और उपलब्धियां'। इसका मुख्य उद्देश्य कब्जे वाले तिब्बत के नए नाम को आधिकारिक बनाना है। यह तिब्बत पर शासन करने के लिए सीपीसी के दिशा-निर्देशों को उजागर करता है। इससे पता चलता है कि बीजिंग ने 'क्षेत्र में विभिन्न उपक्रमों में सर्वांगीण प्रगति और ऐतिहासिक सफलता' हासिल की है। बेशक, यह सम्राट शी की प्रशंसा करते हुए कहता है, '२०१२ में आयोजित १८वीं सीपीसी राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद से अब तक की अवधि में ज़िज़ांग (तिब्बत) ने अभूतपूर्व विकास और बड़े बदलाव का अनुभव किया है, जिससे लोगों को अधिक ठोस लाभ मिला है।'स्वेत -पत्र में आंकड़े देकर समझाया गया है कि, '२०२२ में जिजांग का सकल घरेलू उत्पाद २१३.२६ अरब युआन (लगभग २९.३ अरब डॉलर) तक पहुंच गया, जो २०१२ के बाद से ८.६ प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर को उजागर करता है। इस अवधि के दौरान क्षेत्र में रेलवे नेटवर्क की लंबाई लगभग दोगुनी हो गई और ५जी नेटवर्क वहां

की सभी काउंटियों और मुख्य टाउनशिप में छा गया है। इस क्षेत्र में गरीबी का भी पूर्ण रूप से खात्मा  हो गया है।

'स्वेत-पत्र की समाप्ति से पहले इसमें कहा गया है कि 'ज़िज़ांग के लोगों ने देश के बाकी हिस्सों के साथ चीनी राष्ट्र के खड़े होने और समृद्ध बनने से लेकर ताकत में बढ़ने तक जबरदस्त परिवर्तन को देखा है और अब संपूर्ण रूप से एक आधुनिक समाजवादी देश के निर्माण की नई यात्रा शुरू कर रहा है।'श्वेत-पत्र में सिवाय 'तिब्बती' विशेषण आने पर या 'तिब्बत एयरलाइंस' जैसे किसी संगठन या संस्था का नाम आने के अलावा कहीं भी 'तिब्बत' शब्द का जिक्र नहीं किया गया है। धर्मशाला स्थित निर्वासित तिब्बती सरकार के केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) ने श्वेत-पत्र को दृढ़ता से खारिज कर दिया और कहा कि यह श्वेत-पत्र 'अस्वीकार्य है और गलत व्याख्या, गलत धारणाओं और झूठ' से भरा पड़ा है।

इसमें आगे बताया गया है कि तिब्बत पर यह १९वां श्वेत- पत्र 'ज़िज़ांग' या 'ज़िज़ांग स्वायत्त क्षेत्र' का प्रयोग करके क्षेत्र की विशिष्ट राजनीतिक पहचान को लगातार कम कर रहा है।

सीटीए के प्रवक्ता तेनज़िन लेक्शे ने इसे 'तिब्बती लोगों का अपमान बताते हुए कहा कि ३२ पन्नों का यह दस्तावेज़ लोगों की आकांक्षाओं के बारे में बात करता है, लेकिन इसमें तिब्बती लोग गायब हैं, उनका जिक्र नहीं है। इसलिए हमें आश्चर्य है कि वे किस तरह की आकांक्षाओं के बारे में बात कर रहे हैं , वे किसकी आकांक्षाओं के बारे में बात कर रहे हैं।'

दिल्ली के लिए भी चिंता की बात है कि चीन ने तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र के पार्टी सचिव वांग जुन्झेंग को काठमांडू और फिर कोलंबो की पांच दिवसीय यात्रा पर भेजकर भारत के पड़ोसियों के साथ 'ज़िज़ांग' नाम को आधिकारिक बना दिया है। 'तिब्बती' प्रतिनिधिमंडल (बिना किसी तिब्बती व्यक्ति के) का काठमांडू के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नेपाली नेशनल असेंबली की उपाध्यक्ष उर्मिला आर्यल ने स्वागत किया।

चीनी विदेश मंत्रालय की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि श्री वांग की यात्रा 'दो देशों के बीच उच्चस्तरीय आदान-प्रदान की अच्छी गति'  बनाए रखने के लिए हुई है।

अपने प्रवास के दौरान श्री वांग ने नेपाली प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' से भी मुलाकात की। श्री दहल के विदेशी मामलों के संबंध सलाहकार रूपक सपकोटा ने कहा, चूंकि हम तिब्बत के साथ एक लंबी सीमा साझा करते हैं, यात्रा के दौरान हमारे अधिकारी और सीपीसी प्रतिनिधिमंडल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के साथ-साथ हमारे प्रधानमंत्री की चीन यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित समझौतों को लागू करने पर भी चर्चा करेंगे।"ज़िज़ांग' प्रतिनिधियों ने उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव से भी शिष्टाचार भेंट की। बाद में उन्होंने उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ, संघीय मामलों और सामान्य प्रशासन मंत्री अनीता देवी साह के साथ-साथ नेशनल असेंबली के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिना से भी मुलाकात की।

'ज़िज़ांग' प्रतिनिधियों ने पोखरा में संयुक्त परियोजनाओं का भी दौरा किया। हालांकि यह स्पष्ट था कि इस दौरे का उद्देश्य केवल और केवल 'ज़िज़ांग'के नाम पर स्वीकृति प्राप्त करना था। इतना ही नहीं, एक दिन बाद (१४ नवंबर को) वांग जुन्झेंग को श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी के साथ कोलंबो में देखा गया। साबरी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, 'विदेश मंत्रालय में चीन के जिजांग स्वायत्त क्षेत्रीय समिति में सीपीसी के सचिव वांग जुन्झेंग से मिलकर खुशी हुई। हमने अन्य क्षेत्रों के अलावा संभावित द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। 'इसका मतलब यह है कि अधिक से अधिक देश अब तिब्बत के लिए 'ज़िज़ांग' नाम का उपयोग कर रहे हैं।

किस्सा कोताह यह है कि 'मानव जाति के लिए साझा भविष्य वाले समुदाय के निर्माण के बारे में श्री शी के मीठे वचनों के बावजूद, तिब्बत जैसे प्राचीन राष्ट्रों के लिए बीजिंग की योजनाओं में कोई जगह नहीं है।'यह मानवता या भारत के लिए अच्छा संकेत नहीं है, जिसकी तिब्बत के साथ लंबी सीमा है। शायद राष्ट्रपति बिडेन चीनी 'तानाशाह' के बारे में सही बोल रहे थे।

*****

भारत तिब्बत सहयोग मंच-असम प्रांत ने 12वीं तवांग तीर्थ यात्रा का आयोजन किया

"तिब्बत मुक्त करो, भारत बचाओ" शीर्षक वाली 5वीं जनजागरण साइकिल यात्रा पश्चिम बंगाल के कोलकाता में शुरू हुई

भारत तिब्बत सहयोग मंच-असम प्रांत ने 12वीं तवांग तीर्थ यात्रा का आयोजन किया

# IMPORTANT NOTICE

Dear Readers,

Firstly, I would like to express my heartfelt appreciation for the overwhelming response and support that we have received from you since the launch of Tibbat Desh Magazine.
Tibbat Desh Magazine is the only monthly Hindi Magazine on current affairs of Tibet which includes news on teachings of His Holiness the Dalai Lama, Current grave situations inside Tibet, Events & activities in Exile and of the Tibetan Freedom movement across the globe.
You must be aware, for the past 2 years, we have been receiving complaints about delay and not obtaining the Tibbat Desh magazine on time to our readers. And also we found that many of our readers either have shifted or changed their existing postal address. Therefore to review the mailing address, we request you to assist us in providing the current postal address at the below mentioned address or email.
We would also request our readers to send their feedbacks and suggestions about the magazine.

Yours Sincerely,

**Tenzin Jorden**
Acting Coordinator
India Tibet Coordination Office

# आवश्यक सूचना

**प्रिय पाठकों,**

सबसे पहले में, आप सभी का बहुत अभार व्यक्त करता हूं कि जब से तिब्बत देश मासिक पत्रिका का विमोचन हुआ आप लोगों का निरंतर समर्थन एवं शानदर भागीदारी रहा है।
तिब्बत देश, तिब्बत की पहली हिन्दी समाचार पत्रिका है, जो तिब्बत के भीतर हो रहे चीनी दमनकारी और क्रूर नीति तथा विश्व स्तर पर परमपावन दलाई लामा के मार्गदर्शन में तिब्बती आंदोलन के बारे में भारत के सरकार और लोगों में समर्थन एवं जानकारी उपलब्ध कराना है।
आप सभी को ज्ञात है कि, पिछले दो वर्षों से, हमारे पठकों का बहुत सारे शिकायतों हमारे इस कार्यलय में प्राप्त हुआ, जिनमें कई का यह कहना था कि उनको तिब्बत देश मिल नही रहा है। साथ ही हमें यह भी जानकारी मिली है कि बहुत सारे पठकों का पता एवं आवास बदल गया है या वहां से रवाना हो चुका है।
इसलिए हम इस पत्रिका का इस बार समीक्षा कर रहे है। और आप सभी से यह निवेदन करता हूं कि अगर आपको तिब्बत देश पत्रिका प्राप्त हो रहे है तो उसकी पुष्टी हमे तुरन्त देने की कष्ट करें। आप इसकी पुष्टी हमारे नीछे लिखे गये पता या ई–मेल पर भेज सकते है।
अतः तिब्बत देश पत्रिका के संदर्भ में अपना राय एवं सुझाव हमे समय समय पर भेजने की कष्ट करें।

सादर आपका

तेनज़िन जॉर्डन
कार्यवाहक समन्वयक, भारत तिब्बत समन्वय केंद्र
नई दिल्ली

**कार्यलय पताः** भारत तिब्बत समन्वय केंद्र, एच–10, द्वितीय मंजील, लाजपत नगर–03, नई दिल्ली–110024
**फोनः** 011–29830578
**ई–मेलः** coordinator@indiatibet.net

जर्मनी की आधिकारिक यात्रा पर हैं डिप्टी स्पीकर डोल्मा छेरिंग तेखांग।

अरुणाचल प्रदेश के तिब्बत समर्थक समूह ने ईटानगर में कार्यकारी निकाय की बैठक।